नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 04, अंक 37, नई दिल्ली, शुक्रवार 15 मई 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

समर्थन और सम्मान कभी भी मांगकर नहीं, बल्कि अपने कर्मों और व्यवहार से कमाया जाता है।

03 बाबा बर्फानी की अमर कहानी, क्यों 12 ज्योतिर्लिंगों से भी खास है अमरनाथ का ये रहस्य
06 डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस अधिकारी: मेहनत से बने या महंगे...
08 सरबजीत सिंह सर्वसम्मति से जिला परिषद के चेयरमैन चुने गए

परिवहन विशेष समाचार पत्र को जिस तरह आप लोगों के सहयोग लगातार पिछले 3 वर्षों से प्राप्त हुआ और दिन प्रतिदिन आपकी आवाज को आगे पहुंचाने में आपका सहयोगी बना उसको देखते हुए परिवहन विशेष समाचार पत्र के प्रबंधक मंडल और ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज लिमिटेड कंपनी द्वारा जनहित, जनकल्याण जनसूचना और जानकारी को और तेजी से भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ सभी राजनीतिक संगठनों को सबसे पहले पहुंचाने के उद्देश्य से अक्टूबर माह से जनता की आवाज का अपना चैनल "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" शुरू करने का निर्णय लिया है।

जल्द आपके बीच में....

परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन

बड़ी खुशखबरी! अब आपकी आवाज गूंजेगी पूरी दुनिया में
परिवहन विशेष समाचार पत्र के सफल 3 वर्षों के बाद अब नई क्रांति

आशा करते हैं जैसे आपने आज के इस दौर मे "परिवहन विशेष समाचार पत्रों" को इतना आगे ले कर जाने में सहयोग दिया उसी प्रकार हमारे द्वारा आपकी आवाज बनने के लिए शुरू किए जा रहे "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" को विश्व का सबसे बड़ा चैनल बनवाएंगे।

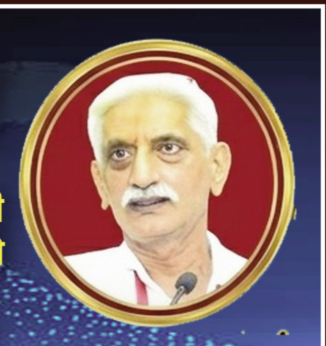

संजय बाठला
मुख्य संपादक

टेम्पल ऑफ़ लिबरलाइज़ेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट, (पंजीकृत) ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन एनजीओ (पंजीकृत)

सांकेतिक फोटो

परिवहन विशेष न्यूज

टोलवा (TOLWA) एक ट्रस्ट/एनजीओ है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है। टोलवा प्रिंट मीडिया RNI अप्रूव्ड दैनिक समाचार पत्र परिवहन विशेष (हिंदी और इंग्लिश) दो भाषाओं में और मंथली न्यूज़ मैगज़ीन पब्लिश और एक न्यूज़ चैनल चलाते हैं।

टोलवा (TOLWA) ट्रांसपोर्ट, रोड सेफ्टी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, पॉल्यूशन कंट्रोल, साइबर सिक्योरिटी और महिला एम्पावरमेंट से जुड़े ज़रूरी मुद्दों पर कॉन्क्लेव और सेमिनार ऑर्गनाइज़ करके जागरूकता फैलाने के लिए बिना थके काम कर रहा है। ये कुछ बड़े मुद्दे हैं जो खास तौर पर आम जनता और पूरे देश को प्रभावित कर रहे हैं।

इसी क्रम मे टोलवा (TOLWA) द्वारा एक सेमिनार/पैनल डिस्कशन ऑर्गनाइज़ करने का प्रस्ताव रखा गया है जिसका टॉपिक होगा

'इंडियन रोड्स डिज़ाइन बनाम सड़कों पर होने वाले एक्सीडेंट'।

"INDIAN ROADS DESIGN viz-a-viz ACCIDENTS ON ROADS"

टोलवा (TOLWA स्टूडेंट्स, एकेडेमिक्स, पॉलिसी मेकर्स, एनफोर्समेंट एजेंसियों, कॉर्पोरेट, वाहन बनाने वालों इत्यादि को पैनल डिस्कशन और पेपर प्रेजेंटेशन के ज़रिए इन मुद्दों पर बात करने के लिए निमंत्रित कर रहा है।

हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेशन को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और सबसे अच्छे स्टूडेंट्स को मेमेंटो दिए जाएंगे।

1. सितम्बर माहः- हंस राज कॉलेज
2. अक्टूबर माहः- मिराण्डा कालेज
3. नवंबर माहः- विज्ञान भवन

कृपया ध्यान दें!!!

नए राशन कार्ड तथा राशन कार्ड में सदस्यों को जोड़ने के आवेदन 15.05.2026 से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (edistrict.delhigovt.nic.in) के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

आपका पूर्व आवेदन लंबित है और 15.05.2026 से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के "Apply Online" मेनू के अंतर्गत "Pending for Submission" अनुभाग में उपलब्ध होगा। कृपया राजस्व विभाग, GNCTD द्वारा जारी पारिवारिक आय प्रमाण पत्र संलग्न कर तथा आवश्यक अपडेट कर आवेदन पुनः जमा करें।

कृपया अपना पारिवारिक आय प्रमाण पत्र तैयार रखें और प्रमाण पत्र सहित आवेदन पुनः जमा करें, ताकि उस पर आगे की कार्यवाही की जा सके।

सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर 1967 पर संपर्क करें।

खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
दिल्ली सरकार

ईंधन संकट पर उबल रहा परिवहन जगत

डीजल-पेट्रोल आपूर्ति में कटौती के आरोपों के बीच ट्रांसपोर्टरों में आक्रोश, देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी - डॉ राजकुमार यादव

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली - देशभर में डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति को लेकर उठ रहे सवाल अब गंभीर राजनीतिक और आर्थिक बहस का रूप लेते जा रहे हैं। परिवहन व्यवसाय से जुड़े संगठनों, ट्रक मालिकों और ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि केंद्र सरकार अप्रत्यक्ष रूप से पेट्रोल पंपों की ईंधन आपूर्ति पर दबाव बनाकर कृत्रिम संकट की स्थिति तैयार कर रही है। उनका कहना है कि डीजल-पेट्रोल की सप्लाई को "येन-केन प्रकारेण" नियंत्रित कर बाजार में भय और अस्थिरता पैदा की जा रही है।

परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों का आरोप है कि आने वाले समय में ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि की आशंका है। उनका कहना है कि यदि जनता पहले से ईंधन की कमी और लंबी कतारों से परेशान होगी, तो बाद में 20, 30 या 50 रुपये तक की संभावित मूल्य वृद्धि पर विरोध कमजोर पड़ जाएगा। इसे एक "सुनियोजित आर्थिक दबाव नीति" के रूप में देखा जा रहा है।

ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद लंबे समय तक देश में ऊंचे दामों पर पेट्रोल और डीजल बेचा गया। उस दौरान तेल कंपनियों और सरकार ने भारी राजस्व अर्जित किया। ऐसे में यदि वर्तमान समय में तेल कंपनियों को कुछ आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है, तो उसका बोझ आम जनता, ट्रक चालकों और परिवहन व्यवसायियों पर डालना न्यायसंगत नहीं है।

इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर राजकुमार

यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, 'उफ्तत्सा' राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्टर सारथी) उपसा ने देशवासियों, परिवहन व्यवसायियों, ट्रक मालिकों, ट्रांसपोर्टरों और सारथी बंधुओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि डीजल केवल वाहन चलाने का माध्यम नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है। यदि ईंधन आपूर्ति और कीमतों पर इसी तरह दबाव बनाया गया, तो इसका सीधा असर खाद्य पदार्थों, कृषि, निर्माण कार्य और आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा।

डॉ. राजकुमार यादव ने कहा कि आज देश का ट्रांसपोर्ट सेक्टर पहले से ही बढ़ते टोल टैक्स, बीमा प्रीमियम, महंगे स्पेयर पार्ट्स और आर्थिक मंदी के दबाव से जूझ रहा है। ऐसे में डीजल संकट ने ट्रक चालकों और ट्रांसपोर्टरों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द स्पष्ट नीति और पारदर्शिता नहीं दिखाई, तो देशभर में परिवहन संगठनों को मजबूर होकर व्यापक आंदोलन करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि यह केवल ट्रांसपोर्टरों का मुद्दा नहीं, बल्कि हर उस नागरिक का सवाल है जिसकी रसोई, खेती, व्यापार और रोजमर्रा की जरूरतें परिवहन व्यवस्था पर निर्भर हैं। उन्होंने सभी ट्रांसपोर्ट यूनियनों, ट्रक मालिक संघों और सारथी संगठनों से संगठित होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की।

हालांकि सरकार या तेल कंपनियों की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन देशभर में बढ़ती चिंता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ईंधन अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि जनजीवन और सामाजिक स्थिरता का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में सरकार की नीति और तेल आपूर्ति व्यवस्था पर पूरे देश की नजर टिकी रहेगी।

दिल्ली में 'मेट्रो डे', वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस की पहल, ट्रैफिक और दबाव कम करने पर जोर

संगिनी घोष

दिल्ली सरकार ने शहर में ट्रैफिक, प्रदूषण और शहरी दबाव कम करने के लिए कई नई पहलें शुरू की हैं। इनमें वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी, ऑनलाइन क्लासेस और 'मेट्रो डे' जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि अब हर सोमवार को "मेट्रो डे" के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी जहां संभव हो, दिल्ली मेट्रो से यात्रा करेंगे।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा

सरकार का उद्देश्य लोगों को निजी वाहनों की बजाय मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

वर्क फ्रॉम होम की सलाह

कार्यालयों और संस्थानों को जरूरत के अनुसार वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अपनाने की सलाह दी गई है, ताकि ट्रैफिक और प्रदूषण कम हो सके।

ऑनलाइन क्लासेस पर जोर

शैक्षणिक संस्थानों को भी अस्थायी रूप से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

सतत शहरी प्रबंधन की दिशा में कदम

इन पहलों को ऊर्जा बचत, बेहतर यातायात प्रबंधन और टिकाऊ शहरी जीवनशैली की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जनभागीदारी की भूमिका अहम

सरकार का मानना है कि इन उपायों की सफलता के लिए नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी होगा।

ऐसे देखें तो दिल्ली की ये नई पहलें भविष्य के ऐसे शहरी मॉडल की ओर इशारा करती हैं, जहां सार्वजनिक परिवहन और डिजिटल कार्य प्रणाली अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मुख्य बिंदु

* दिल्ली सरकार ने नई व्यवस्थाओं की घोषणा की
* हर सोमवार होगा 'मेट्रो डे'
* मंत्री और अधिकारी दिल्ली मेट्रो का उपयोग करेंगे
* वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी जारी
* ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा
* टिकाऊ शहरी प्रबंधन और जनभागीदारी पर फोकस।

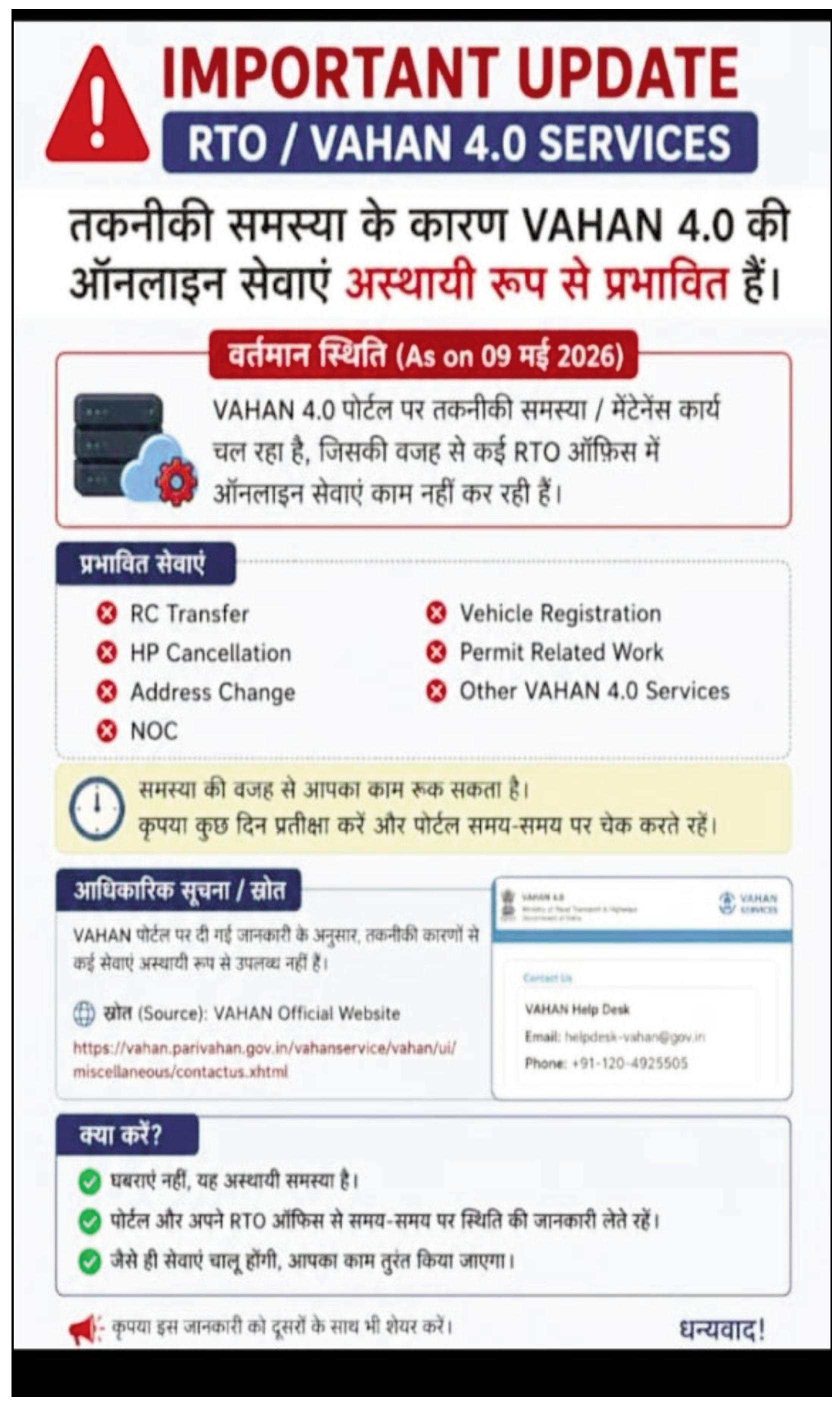

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत
https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा विचार :अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध सिंडिकेट्स का नया हॉटस्पॉट श्रीलंका

पिंकी कुंडू

श्रीलंका अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध सिंडिकेट्स का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। इसका क्षेत्र अवैध कॉल सेंटर संचालन के माध्यम से बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के लिए तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। कंबोडिया की तरह, श्रीलंका भी अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध का केंद्र बनने के खतरे बढ़ रहे है।

हाल ही में हुई कार्रवाई ने समस्या की गंभीरता उजागर की: 198 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 173 भारतीय और 25 नेपाली शामिल थे। इन पर वीज़ा का दुरुपयोग, अवैध रोजगार, प्रतिबंधित सामान रखने और विदेशों में पीड़ितों को निशाना बनाने वाले संगठित साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क में भागीदारी के आरोप लगे।

कार्रवाई से जुड़े मुख्य तथ्य

– कुल गिरफ्तारियां: 198 विदेशी (173 भारतीय, 25 नेपाली)

– हॉटस्पॉट: गाले, हिक्काडुवा, मिडिगामा (दक्षिणी रिसॉर्ट क्षेत्र)

– आयु समूह: मुख्यतः 25–35 वर्ष

– आरोप:

o पर्यटक वीज़ा का दुरुपयोग (ओवरस्टे, अवैध रोजगार)

o ड्यूटी फ्री प्रतिबंधित सामान (सिगरेट) रखना

o साइबर अपराध गतिविधियाँ (धोखाधड़ी, घोटाले, ऑनलाइन शोषण)

– प्रवृत्ति: जनवरी 2026 से अब तक श्रीलंका में 628 विदेशी साइबर अपराध के लिए गिरफ्तार

(Modus Operandi):

– श्रीलंका में प्रवेश: अल्पकालिक टूरिस्ट परमिट पर प्रवेश।

– धोखाधड़ी केंद्र: लैपटॉप और मोबाइल फोन का उपयोग कर अस्थायी स्कैम सेंटर स्थापित करना।

– लक्ष्य: ऑनलाइन संचार प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से विदेशों में पीड़ितों को निशाना बनाना।

– सबूत बरामद: गाले में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 58 कंप्यूटर और 79 मोबाइल फोन जब्त किए।

साइबर अपराध संचालन की प्रकृति

प्राधिकरणों का कहना है कि ये समूह अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट्स से जुड़े थे जो श्रीलंका की कनेक्टिविटी और वीज़ा पहुँच का लाभ उठा रहे थे। उनकी गतिविधियाँ शामिल थीं:

1. ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी – नकली निवेश प्लेटफ़ॉर्म, ऋण घोटाले, ट्रेडिंग धोखाधड़ी
2. डिजिटल संचार घोटाले – अधिकारियों का प्रतिरूपण, "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटाले, वीडियो कॉल के माध्यम से वसूली
3. क्रॉस बॉर्डर सिंडिकेट संचालन – VoIP, एनक्रिप्टेड ऐप्स और सोशल मीडिया का उपयोग कर भारत और अन्य देशों में पीड़ितों को निशाना बनाना
4. अवैध कॉल सेंटर – पर्यटन व्यवसायों के रूप में छिपे, अक्सर चीनी और दक्षिण पूर्व एशियाई नेटवर्क से जुड़े

जोखिम और निहितार्थ

– क्षेत्रीय सुरक्षा खतरा: श्रीलंका का ढीला वीज़ा नियम साइबर अपराध सिंडिकेट्स को आकर्षित कर रहा है

– भारत की संवेदनशीलता: बड़ी संख्या में भारतीयों की संलिप्तता दिखाती है कि अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी नेटवर्क सक्रिय रूप से भर्ती कर रहे हैं

– कानून प्रवर्तन चुनौती: अल्पकालिक वीज़ा धारकों की गुप्त साइबर गतिविधियों की निगरानी कठिन बनी हुई है

सुझाए गए प्रतिविधान

– कड़े वीज़ा निरीक्षण: भारत–श्रीलंका संयुक्त निगरानी तंत्र

– क्रॉस बॉर्डर साइबर टास्क फोर्स: भारतीय पुलिस, CERT In और श्रीलंकाई पुलिस का सहयोग

– जन जागरूकता अभियान: नागरिकों को विदेशी कॉल सेंटर से उत्पन्न घोटालों के बारे में शिक्षित करना

– कानूनी कार्रवाई: आईटी एक्ट और आईपीसी प्रावधानों के तहत तेज़ी से प्रत्यर्पण और अभियोजन

– अंतरराष्ट्रीय सहयोग: यूरोपोल शैली की संयुक्त जांच टीमें बनाना

गिरफ्तारियां यह दर्शाती हैं कि भारतीय नागरिक श्रीलंका से संचालित वैश्विक साइबर अपराध सिंडिकेट्स में फँसते जा रहे हैं। उनकी गतिविधियाँ—धोखाधड़ी, वसूली और अवैध कॉल सेंटर संचालन—भारत की साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए कड़े वीज़ा निरीक्षण और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग की दोहरी रणनीति आवश्यक है।

कैप्नोसाइटोफागा संक्रमणः पालतू जानवरों के काटने और लार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

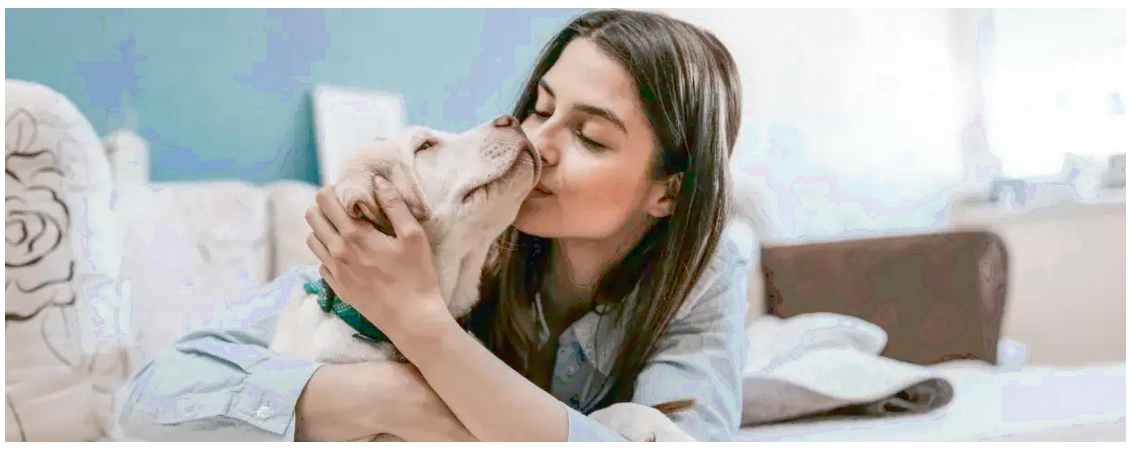

एक प्रकार के बैक्टीरिया का समूह है, जो सामान्यतः कुत्तों और बिल्लियों के मुंह में पाया जाता है, तथा कभी-कभी मनुष्यों में भी मौजूद हो सकता है। अधिकांश परिस्थितियों में ये बैक्टीरिया हानिरहित होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये गंभीर एवं जानलेवा संक्रमण उत्पन्न कर सकते हैं, विशेषकर कुत्ते या बिल्ली के काटने, खरोंचने अथवा उनकी लार के संपर्क में आने के बाद।

कैप्नोसाइटोफागा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

यह संक्रमण प्रायः कुत्ते के काटने से संबंधित पाया जाता है।

निम्न व्यक्तियों में संक्रमण गंभीर रूप धारण कर सकता हैः

वृद्ध लोग

मधुमेह (डायबिटीज) के मरीज

अत्यधिक शराब सेवन करने वाले व्यक्ति

कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग

जिन व्यक्तियों की तिल्ली (Spleen) निकाली जा चुकी हो

संक्रमण के लक्षण

संक्रमण के लक्षण संपर्क के 1 से 8 दिनों के भीतर दिखाई दे सकते हैं, जैसेः

बुखार

घाव के आसपास लालिमा या सूजन

उल्टी या दस्त

मांसपेशियों अथवा जोड़ों में दर्द

त्वचा पर फफोले या रंग परिवर्तन

भ्रम या मानसिक असमंजस

सेप्सिस (रक्त संक्रमण)

गंभीर परिस्थितियों में यह संक्रमण निम्न जटिलताओं का कारण बन सकता हैः

सेप्टिक शॉक

गैंग्रीन

विभिन्न अंगों का फेल होना

मेनिन्जाइटिस

निदान (Diagnosis)

चिकित्सक निम्न माध्यमों से संक्रमण की पहचान करते हैंः

रक्त परीक्षण

घाव की कल्चर जांच

पशु संपर्क या काटने का चिकित्सकीय इतिहास

उपचार (Treatment)

उपचार में सामान्यतः शामिल हैंः

पेनिसिलिन समूह की एंटीबायोटिक दवाएं

गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती

पशु के काटने के बाद घाव की तुरंत एवं अच्छी तरह सफाई

बचाव (Prevention)

पशु के काटने या खरोंचने के बाद घाव को तुरंत साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं।

विशेषकर गहरे घाव होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें।

उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को पालतू पशुओं की लार एवं काटने से अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

यद्यपि कैप्नोसाइटोफागा संक्रमण दुर्लभ है, लेकिन समय पर उपचार न मिलने पर यह अत्यंत गंभीर और जानलेवा सिद्ध हो सकता है। इसलिए जागरूकता, सतर्कता और शीघ्र चिकित्सा अत्यंत आवश्यक है।

नकली या मिलावटी खाद्य पदार्थों से हो रही अनेकों बीमारियां....

भारत में खाद्य पदार्थों, दवाइयों तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं में मिलावट (Adulteration) एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक समस्या बन चुकी है। मिलावट केवल आर्थिक धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि यह सीधे लोगों के स्वास्थ्य, जीवन और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नकली या मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारण हृदय रोग, कैंसर, किडनी एवं लीवर की बीमारियाँ, हार्मोनल असंतुलन तथा अनेक गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

इस प्रकार के अपराध करने वालों के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि समाज में भय और जागरूकता दोनों उत्पन्न हों। हालांकि, किसी भी लोकतांत्रिक और सभ्य समाज में दंड कानून एवं संविधान के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार, प्रशासन और न्याय व्यवस्था मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कानून, त्वरित जांच और प्रभावी दंड सुनिश्चित करें। दुर्भाग्यवश, कई बार कुछ मंत्री, अधिकारी अथवा नीति-निर्माता मिलावट से होने वाले दीर्घकालीन दुष्प्रभावों और जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर असर को पर्याप्त गंभीरता से नहीं समझ पाते। यही कारण है कि इस विषय पर व्यापक जनजागरण, वैज्ञानिक जानकारी और कठोर प्रशासनिक इच्छाशक्ति की अत्यंत आवश्यकता है।

स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु यह आवश्यक है कि सरकार, चिकित्सक, वैज्ञानिक, मीडिया और आम नागरिक सभी मिलकर मिलावट के विरुद्ध एक सशक्त अभियान चलाएँ तथा शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थों को प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार बनाया जाए।

उल्टी जैसा मन (Nausea) हो रहा है? 'सोंठ' का पाउडर जीभ पर रखते ही आराम!

पिंकी कुंडू

वैज्ञानिक कारणः

1. सोंठ में जिंजरल्स और शोगोल्स होते हैं जो ताजे अदरक से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं

2. यह पेट की नसों को शांत करते हैं और गैस्ट्रिक खालीपन को तेज करते हैं, जिससे उल्टी का सिग्नल दिमाग तक जाना बंद हो जाता है

आयुर्वेदिक कारणः

1. सोंठ 'आम-पाचक' है

2. यह 'कफ' को काटती है जो मितली का मुख्य कारण है

3. बिना शहद के सीधे जीभ पर रखने से यह लार ग्रंथियों को उत्तेजित करती है और तुरंत असर दिखाती है

फायदेः

1. मतली शांतः सफर में या प्रेगनेंसी (डॉक्टर की सलाह पर) में बेस्ट

2. भूखः मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा

3. गैसः पेट का भारीपन हटेगा

फॉलो करने की विधिः

1. 1 चुटकी सोंठ पाउडर लें

2. इसे जीभ के बीच में रखें

3. धीरे-धीरे लार के साथ अंदर जाने दें

नुकसानः

1. बहुत तीखा होता है, बच्चे शायद न सह पाएं (उन्हें शहद के साथ दें)

2. गले में जलन हो सकती है, बाद में पानी पी लें

3. अल्सर वाले लोग अवॉयड करें

अल्ट्रा - प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ किडनीक्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ का कारक

पिंकी कुंडू

उभरते हुए वैज्ञानिक प्रमाण इस बात का स्पष्ट समर्थन करते हैं कि अल्ट्रा - प्रोसेस्ड स्नैक्स और सामान्य रूप से अल्ट्रा - प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ किडनी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, विशेष रूप से क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ (किडनीक्रॉनिक किडनी डिज़ीज़) के जोखिम को बढ़ाकर।

अल्ट्रा - प्रोसेस्ड फूड्स में वह सभी आम खाद्य पदार्थ शामिल हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा में खाते हैं — जैसे पैकेट वाले चिप्स, बिस्कुट, मीठे शीतल पेय, इंस्टेंट नूडल्स, प्रोसेस्ड मांस, टॉफ़ियाँ, कैंडीज़, और तैयार - खाने वाले नमकीन या तले हुए आइटम।

यह खाद्य पदार्थ औद्योगिक रूप से बनाए जाते हैं, जिनमें अत्यधिक नमक, चीनी, अस्वस्थ वसा, फॉस्फेट, कृत्रिम रंग - सुगंध और अन्य रासायनिक संपादन होते हैं, जबकि इनका पोषण मूल्य बहुत कम होता है।

कई बड़े वैज्ञानिक अध्ययनों और कई अध्ययनों का संयुक्त विश्लेषण (मेटा - एनालिसिस) से यह संबंध स्पष्ट हुआ है कि अधिक अल्ट्रा - प्रोसेस्ड फूड्स सेवन किडनी को गंभीर हानि से जोड़ता है।

एक प्रमुख दीर्घकालिक अध्ययन, जिसमें 14,000 से अधिक वयस्कों को लगभग 24 वर्षों तक फॉलो किया गया, यह दर्शाता है किः जिन लोगों ने सबसे अधिक अल्ट्रा - प्रोसेस्ड फूड खाए, उनमें किडनीक्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ होने का जोखिम 40% अधिक था।

प्रतिदिन अल्ट्रा - प्रोसेस्ड फूड्स की हर अतिरिक्त सर्विंग के साथ किडनीक्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ का जोखिम लगभग 10% बढ़ जाता है।

कई अध्ययनों का संयुक्त विश्लेषण (मेटा-एनालिसिस) बताते हैं किः अधिक अल्ट्रा - प्रोसेस्ड फूड्स सेवन से लगभग 30% तक किडनीक्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ का जोखिम बढ़ता है और यह प्रभाव डोज़ - रिस्पॉन्स जैसा है — यानी जितना अधिक सेवन, उतना अधिक खतरा (उदाहरणः अल्ट्रा - प्रोसेस्ड फूड्स सेवन में 10% वृद्धि → किडनीक्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ जोखिम में ₹7% वृद्धि)।

जिन लोगों को पहले से किडनीक्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ है, उनमें अधिक अल्ट्रा - प्रोसेस्ड फूड्स खाने सेः

1. किडनी की कार्यक्षमता तेज़ी से गिरती है,

2. मृत्यु का खतरा बढ़ता है, और

3. जटिलताएँ बढ़ती हैं — जैसे इंसुलिन रेज़िस्टेंस, उच्च रक्तचाप, रक्त में फॉस्फेट का बढ़ना (हाइपरफॉस्फेटेमिया) आदि।

इन नुकसानों के पीछे कई जैविक कारण हैंः

1. अधिक सोडियम → रक्तचाप बढ़ाता है (किडनीक्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ का बड़ा कारण),

2. फॉस्फेट एडिटिव्स → रक्त वाहिकाओं और किडनी को नुकसान,

3. रासायनिक एडिटिव्स → सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस,

4. कम फाइबर → आंतों के माइक्रोबायोम को बिगाड़ता है, और

5. कुल मिलाकर खराब आहार → मोटापा, मधुमेह और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो किडनीक्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ के मुख्य जोखिम कारक हैं।

जो लोग "मानवता से प्रेम करने वाले" हैं—अर्थात जो मानव स्वास्थ्य और समाज की भलाई की चिंता करते हैं — उनके लिए यह एक गंभीर जन - स्वास्थ्य संकट है, क्योंकि कई देशों में आज कुल कैलोरी का लगभग 60% हिस्सा अल्ट्रा - प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से आ रहा है, जिससे किडनीक्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ जैसी रोकथाम योग्य बीमारियाँ तेज़ी से फैल रही हैं।

अच्छी खबर यह है कि यदि प्रतिदिन सिर्फ़ एक सर्विंग अल्ट्रा - प्रोसेस्ड फूड्स को हटाकर उसकी जगह कम - प्रोसेस्ड या प्राकृतिक खाद्य पदार्थ फल, सब्ज़ियाँ, मेवे, घर का बना भोजन लिया जाए, तो किडनी रोग का जोखिम कम किया जा सकता है।

विस्तृत व्याख्या, सरल शब्दों मेंः अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाना शरीर को "धीरे - धीरे ज़हर" देने जैसा है, और किडनी इस ज़हर को छानते - छानते थक जाती है।

किडनी का काम हैः

1. रक्त को साफ़ करना

2. नमक, फॉस्फेट और विषैले तत्व बाहर निकालना

लेकिन अल्ट्रा - प्रोसेस्ड फूड्स मेंः

नमक और फॉस्फेट इतना ज़्यादा होता है कि किडनी पर लगातार अतिरिक्त दबाव पड़ता है समय के साथ यह दबाव स्थायी क्षति (किडनीक्रॉनिक किडनी डिज़ीज़) में बदल सकता है। इसलिए किडनीक्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ को अक्सर "साइलेंट किलर" कहा जाता है — यह धीरे-धीरे बढ़ता है और जब लक्षण दिखते हैं, तब तक किडनी काफ़ी हद तक खराब हो चुकी होती है।

नवीनतम विकास और ट्रेंड्स (नवीनतम घटनाक्रम – 2024–2025 तक) डब्लूएचओ और अंतरराष्ट्रीय नेफ्रोलॉजी संगठनों ने अब स्पष्ट रूप से सलाह दी है किः अल्ट्रा - प्रोसेस्ड फूड का सेवन सीमित करना किडनी, हृदय और मेटाबॉलिक बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक है।

नए न्यूट्रिशन गाइडलाइन्स मेंः "फूड प्रोसेसिंग लेवल" को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है जितना कैलोरी या फैट को

कई देशों मेंः फ्रंट - ऑफ - पैक चेतावनी लेबल (ज़्यादा नमक / ज़्यादा चीनी) लागू या प्रस्तावित हैं ताकि लोग अल्ट्रा - प्रोसेस्ड फूड्स के खतरे समझ सकें

निष्कर्ष

1. जो खाना जितना ज़्यादा प्राकृतिक, उतना ज़्यादा सुरक्षित।

2. जो खाना जितना ज़्यादा पैकेट - फैक्ट्री वाला, उतना ज़्यादा ख़तरनाक।

शरीर में यह 10 संकेत मौजूद हैं, तो समझिए आपकी सेहत अंदर से मज़बूत है - बिना किसी दवा के

पिंकी कुंडू

शरीर जब सही संतुलन में होता है, तो वह खुद छोटे - छोटे संकेत देता है। इन संकेतों से जान सकते हैं कि पाचन, इम्यून सिस्टम, हार्मोन और ऊर्जा स्तर ठीक है या नहीं।

1. बाल और नाखून जल्दी बढ़ते हैं यह दर्शाता है कि शरीर को पर्याप्त प्रोटीन, मिनरल्स और पोषण मिल रहा है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है।

2. सुबह आसानी से नींद खुल जाती है इसका मतलब है कि आपकी बॉडी क्लॉक सही चल रही है और हार्मोन संतुलन में हैं।

3. बार-बार सर्दी, खांसी या फ्लू नहीं होता यह मजबूत इम्यून सिस्टम का संकेत है, जो संक्रमण से लड़ने में सक्षम है।

4. रोज़ाना बिना दर्द के पेट साफ़ होता है यह बताता है कि आपका पाचन तंत्र और आंतें स्वस्थ हैं।

5. चलने या सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस नहीं फूलती यह दिल और फेफड़ों की अच्छी क्षमता और सहनशक्ति को दिखाता है।

6. स्किन साफ़, स्मूद और नेचुरल चमक वाली रहती है इसका मतलब है कि शरीर डिटॉक्स ठीक से कर रहा है और पानी की कमी नहीं है।

7. खाने के बाद गैस, जलन या भारीपन नहीं होता यह अच्छे मेटाबॉलिज्म और संतुलित ब्लड शुगर का संकेत है।

8. जोड़ों या पीठ में बेवजह दर्द नहीं रहता यह दर्शाता है कि शरीर में सूजन कम है और मांसपेशियाँ लचीली हैं।

9. तनाव में भी खुद को कंट्रोल कर पाते हैं यह मजबूत नर्वस सिस्टम और मानसिक संतुलन को दर्शाता है।

10. नींद गहरी आती है और सुबह तरोताज़ा महसूस होता है इसका मतलब है कि शरीर की रिकवरी और हार्मोन रिपेयर सही हो रही है।

अगर इनमें से ज़्यादातर संकेत आपमें हैं, तो आपकी सेहत सही दिशा में है। सेहत को बनाए रखना ही असली इलाज है।

इंसान का मनोवैज्ञानिक जीवविज्ञान (नेचुरल बायोलॉजी) आखिर क्या खाने के लिए बना है

पिंकी कुंडू

इंसान का मनोवैज्ञानिक जीवविज्ञान (नेचुरल बायोलॉजी) आखिर क्या खाने के लिए बना है यह सवाल बहुत पुराना है, जैसेः-

1. गाय घास खाती है,

2. शेर मांस खाता है,

3. वैसे ही इंसान क्या खाने के लिए बना है ? फल, सब्ज़ियाँ या जानवरों का मांस ?

4. इसका जवाब धर्म में नहीं, बल्कि क्रमागत उन्नति में छिपा है।

आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले, जब डायनासोर खत्म हो चुके थे और पृथ्वी धीरे - धीरे वापिस पनप रही थी, तब धरती पर घने जंगल फैले हुए थे। इन जंगलों में हर तरफ फल ही फल थे।

उसी समय में एक नया जीव विकसित हुआ,

* आकार में छोटा

* दिखने में चूहे और गिलहरी का मिश्रण और

* पंजे काफ़ी हद तक आज के इंसान जैसे।

इस जीव का नाम था पुर्गेटोरियस। यही दुनिया का पहला मनुष्य - सदृश जानवर माना जाता है, यानी आज के सारे बंदर, सारे वानर और इंसान, हम सबका पहला सामान्य पूर्वज।

पुर्गेटोरियस कोई शिकारी नहीं था, उसके पास नुकीले दाँत नहीं थे, ना ही तेज़ नाखून, और ना ही शिकार करने की कोई प्रणाली। वह पेड़ों पर रहता था और ज़्यादातर फल खाता था।

यहीं से एक अहम बात समझ आती है कि हमें फल मीठे क्यों लगते हैं ? वजह यह है कि फल हमारा सबसे पुराना खाना है। हमारा दिमाग और शरीर लाखों सालों से फल को ऊर्जा के स्रोत के रूप में पहचानता आया है।

अब हम इंसानी शरीर की बनावट को देखते हैं।

1. हमारे दाँत गाय जैसे पूरी तरह समतल भी नहीं हैं और

2. शेर जैसे बेहद नुकीले भी नहीं।

3. हमारी आंतें मांसाहारी से लंबी हैं लेकिन शाकाहारी जितनी लंबी नहीं।

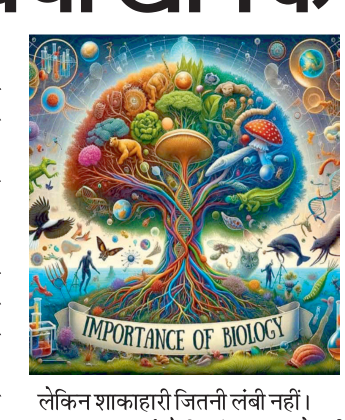

इसका अर्थ है कि इंसान ना तो पूरी तरह मांसाहारी है और ना ही पूरी तरह शाकाहारी। इंसान सर्वाहारी है, यानी जिसमें सब कुछ खाने की क्षमता है।

हमको यहाँ एक ज़रूरी फर्क समझना चाहिए। "सब कुछ खाने की क्षमता" और "सब कुछ खाने के लिए बना होना" एक जैसी बातें नहीं हैं।

इंसान की आधार प्रणाली फल, जड़ें, बीज और पौधों के लिए बना था। मांस बाद में आया, जब जंगल कम हुए, खाना अपर्याप्त हुआ और उत्तरजीविता के लिए नए रास्ते अपनाने पड़े। यानी मांस हमारी शुरुआत नहीं था, बल्कि मजबूरी बना।

यही कारण है कि फल हमें तुरंत ऊर्जा देते हैं, आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और शरीर उन्हें बिना संघर्ष के स्वीकार कर लेता है। शरीर उन्हें पहचानता है, क्योंकि वह उन्हें लाखों सालों से जानता है।

निष्कर्ष इंसान का मनोवैज्ञानिक जीवविज्ञान (नेचुरल बायोलॉजी) फल और पौधों को आधार बनाकर विकसित हुआ है और ज़रूरत पड़ने पर बाकी चीज़ें खाने की क्षमता उसमें जुड़ी।

इंसान का शरीर संतुलन के लिए बना है किसी एक चरम के लिए नहीं। शायद इसी वजह से जब इंसान अपने पुराने, प्राकृतिक खाने से बहुत दूर चला जाता है, तो शरीर पहले चेतावनी देता है और फिर बीमारी,

"क्योंकि जीवविज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता"

सौजन्यः- अवधेश प्रताप सिंह कानपुर

बाबा बर्फानी की अमर कहानी: क्यों 12 ज्योतिर्लिंगों से भी खास है अमरनाथ का ये रहस्य?

हिंदू धर्म में भगवान शिव को 'अनंत' माना गया है, जिनका न आदि है और न ही अंत। उनके विभिन्न स्वरूपों में अमरनाथ में स्थित बाबा बर्फानी का स्वरूप सबसे अलौकिक और विस्मयकारी माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि मोक्ष प्राप्ति का एक द्वार भी मानी जाती है।

अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची में शामिल न होने के बावजूद, अमरनाथ यात्रा को सबसे कठिन और महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसका उत्तर छुपा है वहां के प्राकृतिक रहस्य और पौराणिक कथाओं में।

अमरेश्वर शिवलिंग का अद्वितीय महत्व: एक प्राकृतिक चमत्कार

अमरनाथ गुफा में स्थापित शिवलिंग को 'अमरेश्वर' भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह स्वयंभू हिमलिंग है। जहां अन्य ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है, वहीं बाबा बर्फानी का निर्माण पूर्णतः प्राकृतिक है।

प्राकृतिक निर्माणः गुफा की छत से बर्फ की बूंदें टपकती हैं, जो धीरे-धीरे ठोस होकर एक विशाल शिवलिंग का आकार ले लेती हैं।

चंद्रमा से संबंधः यह दुनिया का इकलौता ऐसा शिवलिंग है जो चंद्रमा की कलाओं के साथ अपना आकार बदलता है। जैसे-जैसे चंद्रमा बढ़ता है, शिवलिंग का आकार भी बढ़ता है और पूर्णिमा के दिन यह अपने पूर्ण आकार में होता है। इसके बाद अमावस्या तक इसका आकार धीरे-धीरे कम होने लगता है।

प्रकटीकरण का समयः यह पावन शिवलिंग विशेष रूप से सावन महीने में प्रकट होता है और रक्षाबंधन (सावन पूर्णिमा) तक इसके दर्शन किए जा सकते हैं।

देवी-देवताओं का साथः इस पवित्र गुफा में केवल महादेव ही नहीं, बल्कि माता पार्वती और भगवान गणेश के भी हिमखंड प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं।

अमरनाथ गुफा का पौराणिक इतिहासः अमरकथा का रहस्य

इस स्थान का नाम 'अमरनाथ' पड़ने के पीछे एक अत्यंत रोचक कथा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह वही एकांत स्थान है जिसे भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य (अमरकथा) सुनाने के लिए चुना था।

महादेव चाहते थे कि जब वे यह कथा सुनाएं, तो कोई भी तीसरा जीवित प्राणी इसे न सुन पाए। इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई त्याग किएः

पहलगाम में अपना नंदी छोड़ा।

शेषनाग झील में अपने गले के सांपों को उतारा।

पंचतरणी में पांचों तत्वों का त्याग किया।

अंत में, इस पावन गुफा में पहुंचकर उन्होंने माता पार्वती को वह कथा सुनाई जिससे मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। इसी कारण इस स्थान को मोक्ष प्राप्ति के लिए परम पवित्र माना जाता है।

अमर कबूतरों का रहस्यः शिव-पार्वती के जीवंत प्रतीक

अमरनाथ गुफा से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य वहां दिखने वाले सफेद कबूतरों का जोड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब भगवान शिव माता पार्वती को अमरकथा सुना रहे थे, तब माता को बीच में नींद आ गई, लेकिन वहां मौजूद कबूतरों के एक जोड़े ने पूरी कथा सुन ली।

कथा सुनने के कारण वे कबूतर अमर हो गए। जब महादेव को इस बात का पता चला, तो वे पहले क्रोधित हुए, लेकिन बाद में उन्होंने उन कबूतरों को वरदान दिया कि वे हमेशा इस गुफा में शिव-पार्वती के प्रतीक के रूप में निवास करेंगे। आज भी, इतनी भीषण ठंड और ऑक्सीजन की कमी वाले क्षेत्र में, जहां पक्षियों का जीवित रहना असंभव है, श्रद्धालुओं को अक्सर ये दो कबूतर दिखाई देते हैं। माना जाता है कि जिसे भी इनके दर्शन होते हैं, वह अत्यंत भाग्यशाली होता है।

अमरनाथ यात्राः अटूट विश्वास और साहस की परीक्षा

अमरनाथ की यात्रा केवल एक धार्मिक भ्रमण नहीं, बल्कि साहस और विश्वास का प्रतीक है। 14,500 फीट की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, हाड़ कंपा देने वाली ठंड और दुर्गम पहाड़ी रास्ते इस यात्रा को दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक बनाते हैं। श्रद्धा की शक्तिः श्रद्धालु इन कठिन रास्तों को पार करते हुए केवल एक ही कामना लेकर जाते हैं—बाबा बर्फानी के दर्शन और अमरत्व का आशीर्वाद।

बाधाओं का नाशः ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस कठिन यात्रा को पूर्ण कर बाबा के दर्शन करता है, उसके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

अलौकिक अनुभवः यहां पहुंचकर जो शांति और ऊर्जा महसूस होती है, वह किसी भी सांसारिक सुख से परे है।

निष्कर्ष

बाबा बर्फानी का यह दरबार हमें सिखाता है कि भक्ति में ही शक्ति है। 12 ज्योतिर्लिंगों के अपने अलग महत्व हैं, लेकिन अमरनाथ का हिमलिंग प्रकृति और अध्यात्म के उस मिलन को दर्शाता है, जो अद्वितीय है। यह स्थान आज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती और भक्तों के लिए मोक्ष का मार्ग बना हुआ है।

अतः, यदि आप भी जीवन में एक बार शांति, साहस और भक्ति के संगम का अनुभव करना चाहते हैं, तो बाबा बर्फानी के दर्शन की योजना अवश्य बनाएं। ₹बम-बम भोले₹ के जयकारों के साथ यह यात्रा आपके अंतर्मन को पवित्र कर देगी।

आज का राशिफल (15/05/2026) –सपम चानू प्रेमा (खगोल–अंकशास्त्री)

मेष
अनुशासन की बेहतर भावना जल्द ही आपके स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक परिणाम दिखाएगी। धन लाभ संभव है और आप सुखी बने रहेंगे। आपकी मेहनत और प्रयास सकारात्मक फल और भावनात्मक संतुष्टि लाएंगे।

वृषभ
आपके सभी रिश्ते कुल मिलाकर काफी सहज और सौहार्दपूर्ण रहने की संभावना है। आपको कुछ अप्रिय अनुभव हो सकते हैं। आप मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं।

मिथुन
आपका कोई मित्र कुछ उपयोगी सुझाव या व्यावहारिक सहायता दे सकता है। आप और अधिक मेहनत करने का साहस जुटा सकते हैं। आपके स्वास्थ्य और रिश्तों में सुधार हो सकता है।

कर्क
आप भविष्य के लिए कोई ठोस प्रतिबद्धता निभाने के लिए तैयार हो सकते हैं। कार्यस्थल पर सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। व्यापारिक सौदों के लिए आज का दिन शुभ हो सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं।

सिंह
खुद को संभालें और एकाग्रता बनाए रखें ताकि आप अपना बकाया काम पूरा कर सकें। अपनी बचत बढ़ाने के तरीके खोजें। काम में धीमी प्रगति हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं।

कन्या
आज हर घंटे या मिनट में परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन मूल सहमति या समझौता आज दृढ़ता से स्थापित हो जाना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार के वाद-विवाद या संघर्ष से बचना चाहिए। आपको कुछ अनावश्यक भय और चिंता का सामना करना पड़ सकता है।

तुला
आज का दिन आपके कामकाजी जीवन का संतोषजनक अंत साबित हो सकता है। आपको कुछ अन्य विदेशी सौदों या व्यवसायों से लाभ प्राप्त हो सकता है। आप अपने जीवनसाथी के साथ स्वस्थ और सुखद संबंध का आनंद ले सकते हैं।

वृश्चिक
हाल के खर्चों के बाद आर्थिक तंगी रहने की संभावना है। बचत के क्षेत्रों पर विचार करने का यह अच्छा समय है। प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए आज का दिन शुभ हो सकता है।

धनु
आज का दिन आपकी क्षमता से अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकता है। काम में आपकी अपेक्षाओं और परिणामों में कुछ अंतर हो सकता है। कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं।

मकर
हाल ही में जिन लोगों से आपका झगड़ा हुआ था, उनसे आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। निवेश में आपको नुकसान हो सकता है। इस समय खर्चों में भी काफी वृद्धि हो सकती है।

कुंभ
सतही रिश्तों में उलझने के बजाय सामाजिक मेलजोल बढ़ाना और नए दोस्त बनाना बेहतर रहेगा। आज आप प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे। आपके स्वास्थ्य और रिश्तों में सुधार हो सकता है।

मीन
किसी भी बोझिल रिश्ते को जारी रखने का कोई फायदा नहीं है। आपके मन में निराशा का भाव व्याप्त है। इस समय आपके सहकर्मी भी ज्यादा सहयोग नहीं दे रहे हैं।

जिस तरह से पुरुष ब्रह्मचर्य उपलब्ध होता है उसी तरह स्त्री कीर्ति को उपलब्ध होती है पूरे जगत की मां बन सकती है

वी बी भरद्वाज

अगर कोई स्त्री कीर्ति को उपलब्ध हो जाए, तो पुरुष के शरीर की कोई भी जरूरत नहीं है। स्त्री के शरीर से ही मोक्ष उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन कीर्ति की प्रक्रिया बिलकुल और होगी।

कीर्ति की प्रक्रिया का अर्थ है कि स्त्री के मन में जितनी तीव्रता से मातृत्व का भाव गहन हो जाए। उसकी साधना मां की साधना होगी। वह पूरे जगत की मां हो जाए। उसके मन में एक ही भाव तरंगित होता रहे, मां होने का। स्त्री होने का भाव छूट जाए, पत्नी होने का भाव छूट जाए, सिर्फ मां होने का भाव गहन होता चला जाए। जिस दिन स्त्री के भीतर मां होने की धारणा इतनी गहन हो जाए कि अगर कोई कामातुर पुरुष भी उसके पास आकर उसके ह्रदय में लग जाए, तो भी उसे अपने बेटे का ही स्मरण हो। वह उसके सिर पर वैसा ही हाथ रख सके, जैसे बेटा उसके पास आ गया हो। उसके भीतर न कोई भय पैदा हो, न कोई चिंता पैदा हो, न कोई घबड़ाहट पैदा हो; वह उसको बेटे की तरह छाती से लगा ले।

और यह अदभुत बात है कि अगर कोई भी स्त्री किसी पुरुष को बेटे की तरह छाती से लगा ले, पुरुष की वासना तत्खण वहीं क्षीण हो जाएगी। वहीं, उसी वक्त क्षीण हो जाएगी। क्योंकि स्त्री का जो आमंत्रण रूप है, वह अगर खो जाए, तो पुरुष तत्काल पाएगा कि वह शांत हो गया है।

इस गुण का नाम कीर्ति है। और जब यह गुण विकसित होता है, तो स्त्री पर भी एक तेज आता है। उस पर भी एक अनूठा सौंदर्य आता है। उस सौंदर्य का कोई संबंध शरीर के सौंदर्य से नहीं है।

कुरूप से कुरूप स्त्री में भी अगर कीर्ति फलित हो जाए, तो उसकी सारी शारीरिक कुरूपता के भीतर से सौंदर्य की आभा फूटने लगती है। उसकी कुरूपता को लोग देख ही न पाएंगे, उसके भीतर का सौंदर्य इतना हावी हो जाएगा। और सुंदरतम स्त्री को भी, अगर कीर्ति न हो, तो उसकी सुंदरता ऊपर चमड़ी पर होती है। और थोडी.ही देर में भीतर की कुरूपता दिखाई पड़नी शुरु हो जाती है।

ओशो, गीता दर्शन # ५. अध्याय # १०

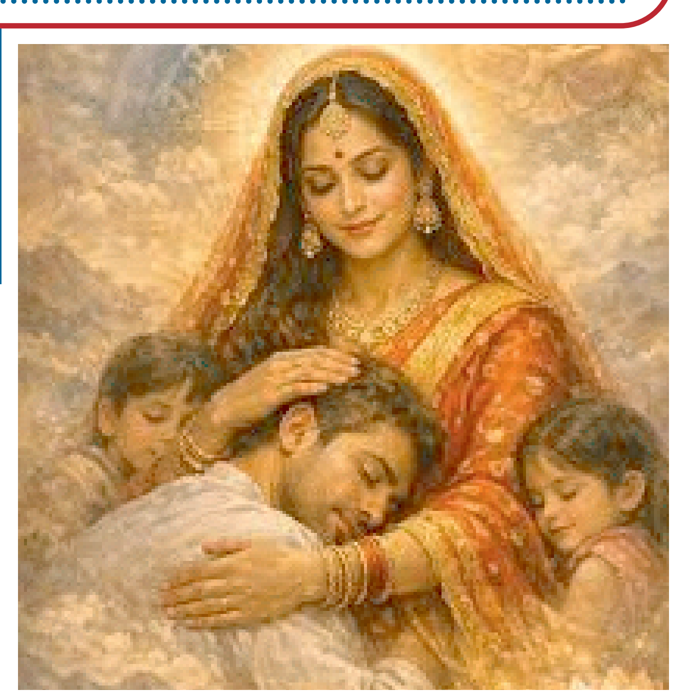

कटनी मध्य प्रदेश की लोकप्रिय समाजसेवी एडवोकेट मंजूषा गौतम को दिल्ली में इंटरनेशनल यूथ लीडरशिप अवार्ड -2026 से सम्मानित किया गया

परिवहन विशेष न्यूज

* दिल्ली के विश्व युवा केंद्र में समाजसेवी अधिवक्ता मंजूषा गौतम को मिला इंटरनेशनल यूथ लीडरशिप वूमेन एंपावरमेंट अवार्ड-2026-------

* समाजसेवी मंजूषा गौतम मध्य प्रदेश का गौरव---

कटनी की बेटी कटनी की बहू ने एक बार फिर से दिल्ली के विश्व युवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय यूथ लीडर लीडरशिप एंड वूमेन एंपावरमेंट अवार्ड प्राप्त करके कटनी जिले का बढ़ाया गौरव -

----

मंजूषा गौतम ने समाज सेवा में लहराया परचम----

* नई दिल्ली में आयोजित विश्व युवा केंद्र के राम कृष्ण बजाज सभागृह में प्रोजेक्ट पॉइंट की ओर से दिल्ली में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार, माय भारत के सहयोग से युवा संवाद का आयोजन किया गया जिसका विषय यूथ इन डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट फॉर विकसित भारत 2047 रहा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत में श्रीलंका की राजदूत महेश्वरी कोलोन ने किया। जिसमें देश भर से लगभग 250चयनित युवा प्रतिनिधियों समाजसेवी एवं युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय यूथ लीडरशिप अवार्ड एवं वूमेन एंपावरमेंट अवार्ड 2026 से समाज सेवी संस्था संघ मध्य प्रदेश कटनी जिले से मुस्कान ड्रीम्स फाउंडेशन की सचिव संस्थापक एडवोकेट समाजसेवी मंजूषा गौतम को प्रोजेक्ट पॉइंट की मध्य प्रदेश की स्टेट प्रेसिडेंट होने के साथ-साथ वुमन एंपावरमेंट को बढ़ावा देने एवं अनेकों सामाजिक कार्यो मैं उत्कृष्ट कार्य करने हेतु मंजूषा गौतम को श्रीलंका उच्च योग नई दिल्ली की माननीय उच्चायुक्त महेश्वरी कॉलोनी केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री उज्जवल ओरम ओडिशा सरकार के विशेष सचिव निहार रंजन दास विश्व युवा केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय शंकर से हैं तथा प्रोजेक्ट पॉइंट उड़ीसा के संस्थापक एवं चेयरपर्सन डॉक्टर संग्राम केसरी सामंत राय के द्वारा शॉल, सर्टिफिकेट, मोमेंटो देकर मंजूषा गौतम को सम्मानित किया गया।

मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व मंजूषा गौतम ने किया। समाजसेवी मंजूषा गौतम वर्तमान समय में कटनी जिले से लेकर मध्य प्रदेश और भारतवर्ष के कोने कोने में अपने सामाजिक कार्यों के द्वारा परचम लहरा रही है। इनके द्वारा किया जाने वाला निशुल्क शिक्षा ,शैक्षिक जागरूकता,, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, एवं शासकीय स्कूलों में निशुल्क शिक्षण सामग्री भेंट करना एवं जरूरतमंद बच्चों की फीस भरना, रक्तदान ,जरूरतमंदों को भोजन वस्त्र आदि का वितरण स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दिव्यांग बेटियों की शादी करवाना ,असहाय जरूरतमंदों झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की सेवा हमेशा से करती आ रही है। एडवोकेट समाजसेवी मंजूषा गौतम को जिला राज्य तथा राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगठनों व सामाजिक संस्थाओं ने लगभग एक हजार संस्थाओं ने सम्मानित किया है। सम्मान मिलने से भावुक हुई मंजूषा सम्मान मिलने पर शहर के सभी वरिष्ठ जनों समाजसेवियों ने उनके परिवार और उनको बहुत-बहुत बधाइयां शुभकामनाएं दी।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव 17 मई से

अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भागवत विदुषी कीर्ति किशोरी अपनी सुमधुर वाणी से श्रवण कराएंगी श्रीमद्भागवत की अमृतमयी कथा

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। छटीकरा रोड़ स्थित श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर अष्टदिवसीय श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव 17 से 24 मई 2026 पर्यन्त अत्यंत श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। जानकारी देते हुए श्रीकृष्ण कीर्ति पत्रिका के प्रधान संपादक, वरिष्ठ साहित्यकार एवं मोटिवेशनल स्पीकर डॉ. सतेन्द्र कुमार जोशी ने बताया कि महोत्सव में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भागवत विदुषी कीर्ति किशोरी जी अपनी सुमधुर वाणी के द्वारा अपराह्न 03 से सायं 07 बजे तक देश-विदेश से आए समस्त भक्तों-श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा श्रवण कराएंगी। महोत्सव के आयोजक दीपक लोहिया एवं नूपुर लोहिया ने सभी भक्तों-श्रृद्धालुओं से इस महोत्सव में उपस्थित रहने का आग्रह किया है।

भव्य भंडारे के साथ संपन्न हुआ पांच दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ

मानपुर। शहरी क्षेत्र के कुर्मी टोला स्थित देवी स्थान के समीप शहीद ईश्वर चौधरी हॉल्ट के पास नवनिर्मित मणिकेश्वर नाथ महादेव मंदिर में आयोजित पांच दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का गुरुवार को भव्य भंडारे के साथ समापन हो गया। आयोजन मानपुर कुर्मी टोला विकास समिति के बैनर तले किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पूजा-अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। समापन अवसर पर आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। भजन-कीर्तन, वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक माहौल से पूरा क्षेत्र भक्तिमय बना रहा। गया नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति सदस्य सह वार्ड संख्या 51 के पार्षद मनोज कुमार ने कहा कि इस धार्मिक आयोजन में दूर-दराज के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक एकता, भाईचारे और आपसी सद्भाव को मजबूत करते हैं। आयोजन को सफल बनाने में मानपुर कुर्मी टोला विकास समिति के सदस्यों की अहम भूमिका रही। इस अवसर पर वार्ड 51 पार्षद मनोज कुमार, डॉ. शशिशेखर सिंह, वार्ड 50 के प्रतिनिधि पंकज सिंह, विकास राव, विनेश राव, मोना राव, बंटी, रीशु पटेल राव, कुंदन, दिनेश राव, आशीष राव, कारू राव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

हर जरूरतमंद को मिलें उसका अधिकार - कालीशंकर

गोरखपुर। वन भारत सिटीजन पार्टी (ओबीसी पार्टी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी ने चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के केशवा पट्टी गांव में 'चौरी चौरा जन कल्याण भवन' बनाने की घोषणा की है। यह घोषणा एक गरीब बुजुर्ग मुलई प्रजापति का मकान आग में जलने के बाद की गई। घटनास्थल का दौरा करने के बाद यदुवंशी ने मुलई प्रजापति को आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने उप जिलाधिकारी से भी बात की और तत्काल सरकारी मदद उपलब्ध कराने का आग्रह किया। यदुवंशी ने इस घटना के बाद सिस्टम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अब चौरी चौरा में एक 'जन अभियान' चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं के माध्यम से आवास दिलाना है, जिनके पास सुरक्षित छत नहीं है। काली शंकर यदुवंशी ने कहा, 'हमारा उद्देश्य केवल एक भवन बनाना नहीं है, बल्कि हर जरूरतमंद को उसका अधिकार दिलाना है। जनता के लिए संघर्ष करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है।' उन्होंने यह भी बताया कि 'चौरी चौरा जन कल्याण भवन' जनसेवा, सामाजिक सहयोग और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक बनेगा। ओबीसी पार्टी का यह कदम दर्शाता है कि पार्टी केवल चुनावी वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक सामाजिक परिवर्तन और चौरी चौरा के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

सीमा पर 62वीं एसएसबी की बड़ी कामयाबी, दुर्लभ रेड सैंड बोआ संग तस्कर दबोचा

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 करोड़

भिनगा। सशस्त्र सीमा बल की 62वीं वाहिनी, भिनगा मुख्यालय के कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण के दिशा-निर्देशन एवं सहायक कमांडेंट अमित शर्मा के नेतृत्व में बाह्य सीमा चौकी सुइया द्वारा वन विभाग ककरदरी रेंज के साथ संयुक्त विशेष गश्त अभियान चलाया गया। यह अभियान गुप्त सूचना के आधार पर ककरदरी वन क्षेत्र में सीमा स्तंभ संख्या 635/10 से लगभग 2.5 किलोमीटर अंदर भारतीय क्षेत्र में संचालित किया गया। अभियान के दौरान संयुक्त टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। उसकी पहचान इरफान खान पुत्र यूनुस खान, निवासी ग्राम अमवा मौलवी, थाना नानपारा, जनपद बहराइच, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक जीवित रेड सैंड बोआ बरामद किया गया, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूची-1 की अत्यंत दुर्लभ एवं संरक्षित प्रजाति मानी जाती है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी इस दुर्लभ सांप की तस्करी ककरदरी वन क्षेत्र से कैसरगंज की ओर करने की फिराक में था। सूत्रों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में रेड सैंड बोआ की कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। बरामद सांप एवं आरोपी को अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए वन विभाग, ककरदरी रेंज को सौंप दिया गया है। 62वीं वाहिनी एसएसबी द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में वन्यजीव तस्करी एवं अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। जवान सीमा सुरक्षा के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण के प्रति भी पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध हैं।

रिद्धनाथ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बालक, हिसार में कक्षा दसवीं के संजू और तमन्ना हरियाणा प्रदेश में दसवें स्थान पर

हरियाणा हिसार: राजेश सलूजा

रिद्धनाथ विद्यालय एक बार फिर से पूरे हरियाणा प्रदेश में दसवां स्थान हासिल करने में कामयाब रहा है और इस बार दसवें पायदान पर एक नहीं दो बच्चे शामिल हैं। कक्षा दसवीं में कुल मिलाकर रिद्धनाथ विद्यालय की तरफ से 65 बच्चों ने बोर्ड की परीक्षा दी और उनमें से 18 बच्चे 90% से ऊपर अंक हासिल करने में कामयाब रहे। कुल मिलाकर 38 बोर्ड मेरिट रही। संस्कृत विषय में 11 बच्चों ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं और सामाजिक में चार बच्चों ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। फिजिकल एजुकेशन में दो बच्चों ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं और विज्ञान में एक बच्चे ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। 14 बच्चों ने अलग-अलग विषयों में 100 में से 99 अंक हासिल किए हैं। विद्यालय का प्रथम और हरियाणा प्रदेश का दसवां स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी संजू पुत्री रमेश कुमार गांव कंडूल से और तमन्ना पुत्री सुखविंदर सिंह गांव बालक से रहे। इन दोनों ही बच्चों ने 500 में से 490 अंक हासिल कर विद्यालय का, अपने माता-पिता का, अपने गांव का, हिसार जिले का और पूरे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। इन दोनों ही बच्चों ने 98% अंक हासिल किए हैं। विद्यालय की ओर से दूसरे स्थान पर रहने वाली छात्रा मुस्कान पुत्री राजेश कुमार गांव पाबड़ा से रही इस छात्रा ने 484 अंक हासिल किए हैं। तीसरे स्थान पर दीक्षा पुत्री जसवीर सिंह गांव बालक से रही जिसने 483 अंक हासिल किए हैं। इस अवसर पर विद्यालय का पूरा स्टाफ और सभी बच्चे अत्यंत उत्साहित नजर आए। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। विद्यालय संचालक मास्टर साधुराम जी रेड्डु ने सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया और उन्हें इसी तरह आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। विद्यालय प्रबंधक जगदीप सिंह ने बच्चों के, अध्यापकों के और अभिभावकों के इस मिले-जुले प्रदर्शन को बहुत सराहा और कहा इस तरह के परीक्षा परिणाम विद्यालय में पिछले लंबे समय से आ रहे हैं और यह सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। विद्यालय प्राचार्य श्री रामअवतार सिंह जी ने सभी बच्चों को, सभी अध्यापकों को और अभिभावकों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी।

हिसार में फर्जी डेंटल क्लिनिक पर छापा 9वीं पास युवक करता था मरीजों का इलाज, सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई में बड़ा खुलासा

हरियाणा हिसार(राजेश सलूजा) :शहर में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर बड़ा खेल सामने आया है। सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने एक गैर-पंजीकृत डेंटल क्लिनिक पर छापा मारकर अवैध रूप से इलाज किए जाने का खुलासा किया है। गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

यह कार्रवाई सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज की इंचार्ज सुनैना के नेतृत्व में की गई। टीम में डेंटल सर्जन डॉ. पुलकित, एएसआई सुरेंद्र और हेड कांस्टेबल जितेंद्र भी शामिल रहे।

बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था क्लिनिक

जानकारी के अनुसार टीम को सूचना मिली थी कि "गेरा डेंटल" नाम से संचालित क्लिनिक में बिना पंजीकरण के इलाज किया जा रहा है। रेड के दौरान पाया गया कि क्लिनिक किसी भी सरकारी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड नहीं था। मौके पर न तो कोई वैध लाइसेंस मिला और न ही ओपीडी रजिस्टर या डॉक्टर से जुड़े आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे।

9वीं पास युवक कर रहा था इलाज

जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि प्रदीप कुमार नामक युवक, जो केवल 9वीं पास बताया गया है, मरीजों की जांच कर रहा था। वह मरीजों को दवाइयां दे रहा था और उनसे फीस भी वसूल रहा था। मौके पर मौजूद मरीजों ने भी इसकी पुष्टि की।

संचालक के दावों पर उठे सवाल क्लिनिक संचालक महेंद्र बजाज ने दावा किया कि क्लिनिक डॉ. तरुण गेरा द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन मौके पर उनके नाम से संबंधित कोई दस्तावेज, बिल या रिकॉर्ड नहीं मिला। इससे क्लिनिक के संचालन को लेकर संदेह और गहरा गया।

इसके अलावा क्लिनिक के पास हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति भी नहीं थी और मेडिकल वेस्ट निपटान की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई।

मरीजों ने भी खोली पोल

रेड के दौरान पहुंचे मरीजों ने बताया कि प्रदीप नाम का युवक ही उनकी जांच करता था, दवाइयां देता था और पैसे लेता था। इससे साफ हो गया कि बिना योग्यता के लोगों का इलाज किया जा रहा था।

पुलिस को सौंपी गई रिपोर्ट

सीएम फ्लाइंग इंचार्ज सुनैना ने कहा कि बिना योग्यता और पंजीकरण के अस्पताल या क्लिनिक चलाना गंभीर अपराध है और इससे लोगों की जान को खतरा होता है। टीम ने पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर पुलिस को सौंप दी है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी।

यू मॉडल ओवरब्रिज काफी सुलभ तथा उपयोगी होगा

परिवहन विशेष न्यूज

गोरखपुर। चौरीचौरा में रेलवे गेट संख्या 147 बी पर एक अंडरपास की मांग को लेकर दुकानदारों व व्यापारियो ने वृहस्पतिवार को विधायक इंजीनियर सरवन निषाद के आवास से लेकर तहसील मुख्यालय तक प्रदर्शन कर पत्रक देकर अंडरपास की मांग की है। चौरीचौरा में भोपा बाजार चौराहे से मुंडेरा बाजार जाने वाले मुख्य मार्ग पर रेलवे क्रासिंग संख्या 147 बी स्थित है। मुंडेरा बाजार में व्यावसायिक गतिविधियों के कारण दूर-दराज से बड़े वाहनों, व्यापारियों तथा जनता का अत्यधिक आवागमन होता है जिसके दृष्टिगत चमड़ा मंडी से लेकर शहीद स्मारक रोड पर निर्माणाधीन यू मॉडल ओवरब्रिज काफी सुलभ तथा उपयोगी होगा। साथ ही, रेलवे क्रासिंग पर एक अंडरपास बनने से मुख्य मार्ग पर स्थित विद्यालयों में आने वाले छात्रों, सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों, एम्बुलेन्स, ठेले, साइकिल, मोटर साइकिल तथा अन्य छोटे वाहन आने में काफी सुगमता हो जायेगी तथा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यापारियो ने विधायक व तहसील के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि जनहित में इस मार्ग पर चमड़ा मंडी से शहीद स्मारक रोड पर निर्माणाधीन यू-मॉडल ओवरब्रिज को ही बनवाया जाय तथा रेलवे क्रासिंग पर एक छोटा अंडरपास बनवाने की मांग की है। व्यापारियो ने तहसील मुख्यालय पर तहसीलदार सत्य प्रकाश गुप्ता को पत्रक देकर अंडरपास बनवाने की मांग की।

टॉपर्स का हुआ जोरदार सम्मान

परिवहन विशेष न्यूज

गोरखपुर। सीबीएसई द्वारा जारी कक्षा 12 के रिजल्ट में चौरीचौरा के सरदार नगर में स्थित वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल का परिणाम शत प्रतिशत रहा। विगत वर्षों की तरह इस बार भी क्लास 10 एवं क्लास 12 के चौरी चौरा टॉपर वर्टेक्स से ही है। जिसमें बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने माता पिता एवं स्कूल एवं चौरी चौरा क्षेत्र का नाम रोशन किया। इसी के साथ बच्चों का प्रतिशत इस प्रकार रहा आर्यन गुप्ता 93%, शान्वी भरद्वाज 90.6%, स्वस्तिका शुक्ला 90.4%, अमृता यादव 90%, रिद्धिमा गुप्ता 88.6% आरुषि सिंह 88.4%, सूरज कुमार 88%, दिव्यांशी 86%, कृष्णा गुप्ता 85.8%, युगल किशोर 85.2%, इमराना यास्मीन 84.2%, आजम खान 83.6%, आस्था पांडे 83.2%, आर्या शर्मा 83.2%, दिव्या 82.4% मोहम्मद अदनान अहमद 82.2%, अंशिका गौड़ 81.2%, नूपुर शर्मा 81%, अंकुर कश्यप 80.4%, और भी कई बच्चो का बेहतर प्रतिशत रहा।

इस अवसर पर स्कूल चेयरमैन अरविंद त्रिपाठी एवं निदेशक तूलिका त्रिपाठी एवं शैलेन्द्र त्रिपाठी ने बच्चो को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। स्कूल प्रिंसिपल आर के मिश्रा ने बच्चो को मिठाई खिला कर प्रसन्नता व्यक्त की इसी के साथ पी एस पटेल, प्रवीण चौरसिया, आशुतोष दुबे, सोम शर्मा एवं सभी स्टाफ ने बच्चो का उत्साहवर्धन किया।

अंकों की अंधी दौड़ और खोता बचपन

— डॉ. प्रियंका सौरभ

"अंकों की इस दौड़ में, बचपन हुआ उदास। कंधों पर उम्मीद का, भारी पड़ा लिबास॥"

भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा को हमेशा से सम्मान और प्रगति का माध्यम माना गया है। शिक्षा व्यक्ति को केवल ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि उसे जीवन जीने की समझ, सामाजिक चेतना और बेहतर भविष्य की दिशा भी प्रदान करती है। किंतु समय के साथ शिक्षा का स्वरूप बदलता गया और आज स्थिति यह हो गई है कि शिक्षा का अर्थ केवल अधिक अंक लाना और प्रतियोगिता में आगे निकलना भर रह गया है। बच्चों का मूल्यांकन उनके व्यक्तित्व, व्यवहार, रचनात्मकता या संवेदनशीलता से नहीं, बल्कि उनकी मार्कशीट के प्रतिशत से किया जाने लगा है। परिणामस्वरूप बचपन दबाव, तनाव और अपेक्षाओं के बोझ तले कराह रहा है।

आज हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा कक्षा में प्रथम आए, सर्वोच्च अंक प्राप्त करे और समाज में प्रतिष्ठित पद हासिल करे। यह इच्छा स्वाभाविक है, क्योंकि हर अभिभावक अपने बच्चों का उज्ज्वल भविष्य चाहता है। समस्या तब शुरू होती है जब यह इच्छा अपेक्षा बन जाती है और अपेक्षा धीरे-धीरे दबाव में बदल जाती है। बच्चे की रुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसे किस क्षेत्र में आनंद मिलता है—इन प्रश्नों पर कम ध्यान दिया जाता है। मुख्य चिंता केवल अंक और रैंक की रह जाती है।

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ने बच्चों के जीवन को अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया है। स्कूल की पढ़ाई के अतिरिक्त कोचिंग, ट्यूशन, ऑनलाइन क्लास और असाइनमेंट ने बच्चों के दिन का अधिकांश समय घेर लिया है। पहले बच्चे शाम को मैदानों में खेलते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, दोस्तों के साथ हँसते-भागते थे, लेकिन आज उनका बचपन पुस्तकों और स्क्रीन के बीच कैद होकर रह गया है। खेल का मैदान अब मोबाइल की स्क्रीन में सिमट गया है और खुलकर हँसने की जगह परिणामों की चिंता ने ले ली है।

हर वर्ष परीक्षा परिणाम आने के बाद समाज का व्यवहार बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को और अधिक प्रभावित करता है। जिन बच्चों के अंक अधिक आते हैं, उन्हें समाज "होनहार" घोषित कर देता है, जबकि अपेक्षाकृत कम अंक पाने वाले बच्चे स्वयं को कमतर समझने लगते हैं। यह तुलना बच्चों के भीतर आत्महीनता पैदा करती है। कई बच्चे तनाव, अवसाद और भय से घिर जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ बच्चे परीक्षा में असफलता के कारण आत्मघाती कदम तक उठा लेते हैं। यह स्थिति केवल शिक्षा व्यवस्था की नहीं, बल्कि पूरे समाज की विफलता का संकेत है।

आज बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव "तुलना" का पड़ रहा है। "देखो, शर्मा जी का बेटा कितना पढ़ता है", "उसके 98 प्रतिशत आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं?"—ऐसे वाक्य बच्चों के मन पर गहरी चोट करते हैं। तुलना कभी प्रेरणा नहीं बनती, बल्कि आत्मविश्वास को कमजोर करती है। हर बच्चा अपनी क्षमता, सोच और प्रतिभा में अलग होता है। कोई संगीत में उत्कृष्ट हो सकता है, कोई खेल में, कोई चित्रकला में और कोई लेखन में। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक सोच केवल डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बनने को ही सफलता का पर्याय मानती है।

यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि क्या केवल अधिक अंक प्राप्त कर लेना जीवन की सफलता की गारंटी है? इतिहास और वर्तमान दोनों इस बात के साक्षी हैं कि अनेक महान व्यक्तियों ने साधारण शैक्षिक उपलब्धियों के बावजूद असाधारण कार्य किए। सफलता केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं आती, बल्कि साहस, धैर्य, रचनात्मकता, संवेदनशीलता और मेहनत से आती है। यदि शिक्षा मनुष्य को अच्छा इंसान नहीं बना पा रही, तो वह अधूरी है।

आज के बच्चे तकनीकी रूप से बहुत तेज हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से अकेले होते जा रहे हैं। माता-पिता दोनों के कामकाजी होने,

संयुक्त परिवारों के टूटने और मोबाइल संस्कृति के बढ़ने से बच्चों को संवाद और भावनात्मक सहयोग कम मिल रहा है। वे अपनी परेशानियाँ किसी से खुलकर कह नहीं पाते। ऐसे में परीक्षा और भविष्य का दबाव उन्हें भीतर से तोड़ देता है। शिक्षा का वातावरण आनंददायक होने के बजाय भय का वातावरण बनता जा रहा है।

कोचिंग संस्थानों की बढ़ती संस्कृति ने भी इस समस्या को गंभीर बनाया है। बड़े-बड़े विज्ञापनों में टॉपर्स के चेहरे दिखाकर बच्चों और अभिभावकों के मन में यह धारणा बना दी जाती है कि सफलता केवल कठिन प्रतिस्पर्धा और लगातार पढ़ाई से ही मिलेगी। बच्चों को मशीन की तरह तैयार किया जा रहा है। उनकी रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। शिक्षा अब सीखने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अंकों की फैक्ट्री बनती जा रही है।

सबसे दुखद स्थिति तब होती है जब बच्चे स्वयं को अपने माता-पिता के सपनों का बोझ समझने लगते हैं। वे डरते हैं कि यदि उनके अंक कम आए, तो वे परिवार को निराश कर देंगे। यह डर उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। कई बार माता-पिता अनजाने में बच्चों को यह महसूस करा देते हैं कि उनका प्यार भी अंकों पर निर्भर है। जबकि बच्चों को सबसे अधिक आवश्यकता बिना शर्त स्वीकार्यता और भावनात्मक सुरक्षा की होती है।

हमें यह समझना होगा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए—मानवता, संवेदनशीलता, नैतिकता और आत्मविश्वास का विकास। यदि कोई बच्चा दूसरों की मदद करना सीखता है, अपने माता-पिता का सम्मान करता है, समाज के प्रति जिम्मेदार बनता है और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, तो वही सच्ची शिक्षा है।

बच्चों को अपनी रुचियों के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यदि किसी बच्चे को संगीत पसंद है, तो उसे संगीत में आगे बढ़ने दिया जाए। यदि किसी को खेल, अभिनय, लेखन, कला या किसी अन्य क्षेत्र में रुचि है, तो उसका सम्मान किया जाए। हर प्रतिभा महत्वपूर्ण है। समाज को यह समझना होगा कि दुनिया केवल डॉक्टर और इंजीनियरों से नहीं चलती, बल्कि कलाकारों, शिक्षकों, किसानों, लेखकों, वैज्ञानिकों, संगीतकारों और खिलाड़ियों से भी समृद्ध होती है।

अभिभावकों और शिक्षकों की जिम्मेदारी यहाँ सबसे अधिक है। बच्चों को डाँटने और डराने के बजाय उन्हें समझना और प्रेरित करना आवश्यक है। यदि बच्चा असफल होता है, तो उसे यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। कई बार जीवन की सबसे बड़ी सफलताएँ असफलताओं से ही जन्म लेती हैं।

विद्यालयों को भी परीक्षा-केंद्रित शिक्षा से बाहर निकलकर व्यक्तित्व विकास, रचनात्मक गतिविधियों और नैतिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को केवल रटने के बजाय सोचने और समझने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के भीतर जिज्ञासा और आनंद जगाए, न कि भय और तनाव।

सरकार और समाज को भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होना होगा। स्कूलों में काउंसलिंग व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। माता-पिता को भी समय-समय पर यह समझाने की आवश्यकता है कि बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालना कितना हानिकारक हो सकता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम शिक्षा और सफलता की परिभाषा बदलें। बच्चे को केवल अंक लाने वाली मशीन नहीं, बल्कि संवेदनशील और रचनात्मक इंसान के रूप में देखें। उसे यह महसूस कराएँ कि उसका मूल्य उसकी मार्कशीट से कहीं अधिक है।

यदि हम सच में आने वाली पीढ़ी को खुश, स्वस्थ और आत्मविश्वासी बनाना चाहते हैं, तो हमें अंकों की अंधी दौड़ से बाहर निकलना होगा। बच्चों को खेलने दीजिए, सपने देखने दीजिए, असफल होने दीजिए और फिर उठकर आगे बढ़ने दीजिए। क्योंकि जीवन केवल परीक्षा परिणामों का नाम नहीं, बल्कि अनुभवों, संघर्षों, संवेदनाओं और रिश्तों का सुंदर संगम है।

अंततः यही कहना उचित होगा कि—

"अच्छे अंक नहीं बड़े, बड़ा बने इंसान।"

(डॉ. प्रियंका सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), कवयित्री एवं सामाजिक चिंतक

कानपुर की चकरपुर सब्जी मंडी में भीषण आग से भारी नुक्सान

सुनील बाजपेई

कानपुर। आज गुरुवार दोपहर यहां के सचेंडी स्थित चकरपुर सब्जी मंडी में अचानक भीषण आग लग गई। आग की शुरुआत चबूतरा नंबर-6 स्थित एक आढ़त से हुई और देखते ही देखते उसने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच आग इतनी तेजी से फैली कि करीब 40 से अधिक दुकानें धू-धू कर जलने लगीं। मौके पर मौजूद आढ़तियों ने पहले खुद आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें बढ़ती देख दुकानों को छोड़कर जान बचाकर भागना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। पहले दो दमकल गाड़ियों को भेजा गया, लेकिन आग की गंभीरता को देखते हुए बाद में आठ फायर टेंडर मौके पर लगाए गए। समाचार लिखे जाने तक दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।

पूर्व मंत्री आलमगीर दो साल बाद जेल से निकले, पत्नी -पुत्र समेत कांग्रेसी नेता, मंत्री ने किया स्वागत

2024मे ईडी के हाथों गिरफ्तार होने पर उनकी सीट से पत्नी निशत आलम जीती थी चुनाव

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम करीब दो वर्ष जेल में रहने के बाद गुरुवार को जेल से बाहर आए. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज वे जेल से बाहर निकले. रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से आलमगीर आलम के बाहर निकलने की खबर के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जेल के बाहर जमा हो गए. यही स्थिति उनके एचईसी स्थित सरकारी आवास के पास दिखीं.

पाकुड़ की विधायक और आलमगीर आलम की पत्नी निशत आलम, अपने पुत्र और पोते के साथ जेल पहुंचीं. जमानत पर रिहाई की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आलमगीर आलम जेल से बाहर निकले. उन्होंने सबसे पहले अपने पोते को दुलारा, इस बीच उनके समर्थक नारा लगाते नजर आए.

विधायक पत्नी निशत आलम के सरकारी आवास पर आलमगीर आलम के पहुंचते ही उनके समर्थकों में उनकी एक झलक पाने के लिए बेताबी दिखी. इस मौके पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, उज्जवल तिवारी सहित कई कांग्रेस नेताओं ने आलमगीर आलम से मुलाकात की. पाकुड़ की विधायक और आलमगीर आलम की पत्नी निशत आलम, अपने पुत्र और पोते के साथ जेल पहुंचीं. जमानत पर रिहाई की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आलमगीर आलम जेल से बाहर निकले. उन्होंने सबसे पहले अपने पोते को दुलारा, इस बीच उनके समर्थक नारा लगाते नजर आए. विधायक पत्नी निशत आलम के सरकारी आवास पर आलमगीर आलम के पहुंचते ही उनके समर्थकों में उनकी एक झलक पाने के लिए बेताबी दिखी. इस मौके पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, उज्जवल तिवारी सहित कई कांग्रेस नेताओं ने आलमगीर आलम से मुलाकात की. कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि आलमगीर आलम की गिरफ्तारी एक राजनीतिक गिरफ्तारी थी और भाजपा के इशारे पर उन्हें करप्शन का गलत मामला बनाकर फंसाया लेकिन सत्य की जीत हुई है. इसके साथ ही ईडी-केंद्र सरकार की पोल खुल गयी है. आज उनकी रिहाई से सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं बल्कि आम जनमानस में भी खुशी है.

पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कठिन समय में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों ने उनको जो समर्थन-सहयोग दिया जिससे उनका मनोबल कभी नहीं टूटा. वह आज उन सभी लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पर उनका भरोसा है और वह कानून का सम्मान करते हैं.

आलमगीर आलम ने अपने आगे की राजनीतिक प्लान को लेकर कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पहले कुछ दिन स्वास्थ्य लाभ करने के बाद आगे की बात आप सबके साथ शेयर करेंगे.

लाख टके का सवाल : एसआईआर या आईएसआर ?

नीलोत्पल बसु, अनुवाद : संजय पराते)

बस यही बात है। स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (एसआईआर) या इंटेंसिव सबवर्ज़न ऑफ़ रोल्स (आईएसआर) — इस चुनावी मौसम में यह सबसे ज़्यादा गरमागरम बहस का विषय है; न सिर्फ़ चुनाव से पहले की गहमागहमी के दौरान, बल्कि शायद उससे भी कहीं ज़्यादा चुनाव के बाद के माहौल में।

अभूतपूर्व एसआईआर : यह संशोधन नहीं, बल्कि व्यवस्था को पलटना है

शुरू से ही, बिहार में ही, एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) विवादों में घिर गया, क्योंकि 24 जून, 2025 को की गई घोषणा से पहले राजनीतिक दलों के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया था — जैसा कि अब तक स्थापित परंपरा रही है। गहन पुनरीक्षण का काम हमेशा एक लंबी अवधि तक चलता रहा है। प्रथम चुनाव आयोग के समय से ही सामान्य सिद्धांत स्थापित था — प्रत्येक नागरिक के लिए मतदान के अधिकार की सार्वभौमिकता; और मतदाता सूची तैयार करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह और विशेष रूप से चुनाव आयोग की थी, ताकि अनुच्छेद 326 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। मसौदा सूची (ड्राफ़्ट रोल) से नाम हटाने की निर्धारित प्रक्रिया आपत्तियों के आधार पर पूरी की जानी थी, जिनकी पुष्टि गृह मंत्रालय के परामर्श से की जानी अनिवार्य थी।

वर्तमान एसआईआर ने घर-घर जाकर गिनती करने की एक प्रक्रिया निर्धारित की थी, जिसके साथ ही एक लिखित आवेदन और 11 दस्तावेज़ों में से कोई एक दस्तावेज़ जमा करना ज़रूरी था। बहुत कम लोगों के पास ये दस्तावेज़ उपलब्ध है। ये दस्तावेज़ न दे पाने का मतलब था वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाना। असल में, इसका मतलब था कि मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होगा, क्योंकि यह एक बिल्कुल नई प्रक्रिया थी, जिसमें बिना दस्तावेज़ वाले नागरिक को गैर-नागरिक मान लिया जाता है और उसका नाम अपने-आप हटा दिया जाता है। यह अनुच्छेद 326 और वोट देने के सार्वभौमिक अधिकार का पूरी तरह से उल्लंघन था। गैर-नागरिकों की पहचान करने की ज़िम्मेदारी गृह मंत्रालय को सौंपी गई थी। लेकिन, सीएए और एनआरसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में नाकाम रहने के बाद, बड़बोले गृह मंत्री ने एक खतरनाक चाल चली। उसने एक तरीका सुझाया : पता लगाओ, नाम हटाओ और देश से निकालो — जिसके लिए एसआईआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया, ताकि बिना दस्तावेज़ वाले नागरिकों को अपराधी ठहराया जाए और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाए।

विपक्षी दलों ने मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाक़ात की, लेकिन उन्हें उस हालत को, जो बड़े पैमाने पर लोगों के मताधिकार से वंचित होने का खतरा पैदा कर रही थी, को सुधारने का आश्वासन दिए बिना ही उनकी बातों को खारिज कर दिया गया। बहरहाल, जहाँ बिहार में हुई एसआईआर की प्रक्रिया ने कई सवाल खड़े किए थे, वहीं बाकी 12 राज्यों में बाद में हुई एसआईआर की प्रक्रिया में मैपिंग का काम बिहार जितना सख़्त नहीं हो पाया। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ कि चुनाव आयोग ने पारदर्शिता नहीं बरती और एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने को सही ठहराने के लिए 2002-03 के मूल आदेश को भी उजागर नहीं किया।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर का कालक्रम और कार्यप्रणाली

ज़ाहिर है, पश्चिम बंगाल में एसआईआर की कवायद शुरू से ही काफ़ी विवादित रही है। मैपिंग चरण से पता चला कि मसौदा संशोधन के दौरान एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, हटाए गए, विस्थापित) श्रेणियों के तहत केवल 58 लाख नियमित विलोपन ही स्थापित किए गए थे। इसके साथ ही, 'अंडर एडजुडिकेशन' (यूए मामले) की न्यायिक समीक्षा के बाद 27 लाख अन्य मतदाता भी अयोग्य घोषित कर दिए गए। ये वही 27 लाख लोग हैं, जो चर्चा के केंद्र में आ गए हैं।

6 अप्रैल तक, लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे, जो एसआईआर प्रक्रिया के शुरू होने से पहले कुल मतदाताओं का लगभग 11.9% थे। मतदान से पहले, बताया गया कि ट्रिब्यूनलों के पास लगभग 34 लाख अपीलें लंबित थीं। इनमें से, 7 लाख अपीलें मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के विरोध में थीं, और 27 लाख अपीलें उन लोगों द्वारा दायर की गई थीं, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। एसआईआर प्रक्रिया के तहत गठित अपीलीय ट्रिब्यूनलों ने 1,607 नामों को वापस मतदाता सूची में शामिल करने की अनुमति दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कुछ चिंताएँ जताईं, और इस बात पर ज़ोर दिया कि उन लोगों द्वारा दायर अपीलों पर विचार करने के लिए एक ₹मज़बूत अपीलीय तंत्र₹ का होना ज़रूरी है, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। जस्टिस बागची ने कहा कि जब पश्चिम बंगाल की बात आई, तो चुनाव आयोग ने दूसरे राज्यों में अपनाई गई प्रक्रिया से हटकर एक नई श्रेणी 'लॉजिकल डिसक्रिपेंसी' (तार्किक विसंगति) शुरू कर दी। जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार एसआईआर मामले में अपनाए गए उस रुख से भी किनारा कर लिया, जिसके तहत यह कहा गया था कि जिन लोगों के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज थे, उन्हें दस्तावेज़ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है।

"किसी उम्मीदवार को चुनाव में हिस्सा लेने से गलत तरीके से रोकना, चुनाव रद्द करने का एक आधार है। लेकिन वोट देने का अधिकार अपने आप में — जब तक कि मतदाताओं की संख्या

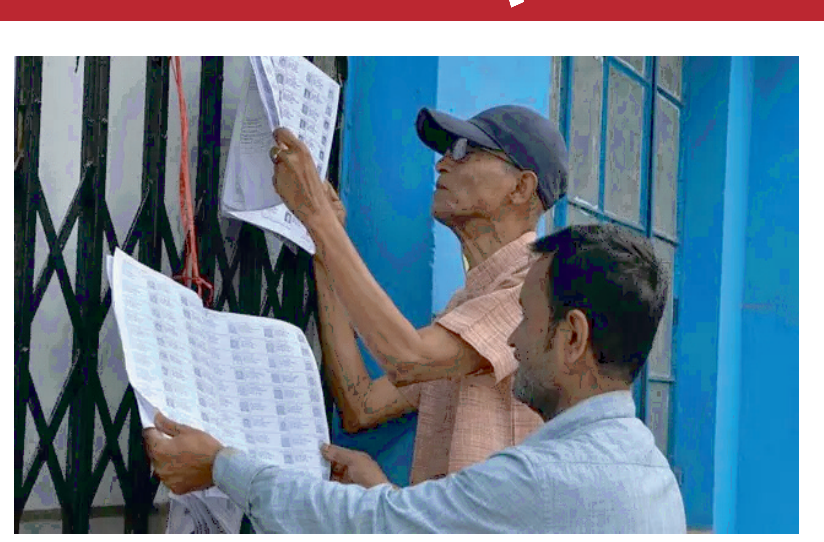

बहुत ज़्यादा न हो — जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 100 के तहत चुनाव रद्द करने के आधारों में से एक नहीं माना जाता। अगर 10% मतदाता वोट नहीं डालते और जीत का अंतर 10% से कम है... तो क्या होगा? मान लीजिए जीत का अंतर 2% है और 15% मतदाता, जिनकी पहचान हो चुकी है, वोट नहीं डाल पाए, तो शायद — हम कोई राय नहीं दे रहे हैं — लेकिन हमें निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि किसी ऐसे जागरूक मतदाता की चिंता, जिसका नाम सही या गलत तरीके से सूची में नहीं है, हमारे ध्यान में नहीं है," जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग से कहा।

बहरहाल, इस चिंता के बावजूद, जस्टिस बागची को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट राज्य के 19 ज़िलों के लिए न्यायिक ट्रिब्यूनलों को कितना बड़ा काम सौंप रहा है। यह व्यवस्था कोलकाता हाई कोर्ट के ज़रिए बनाई गई थी, लेकिन चुनावों के पहले चरण तक यह ठीक से शुरू भी नहीं हो पाई थी। उन लोगों के मानसिक कष्ट की तो बात ही छोड़िए, जो पूरी तरह से चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई एसआईआर की गलत योजना और समय-सीमा के कारण इस संदिग्ध 'यूए' श्रेणी में आ गए थे। जस्टिस बागची की यह उम्मीद कि अगर 70% काम भी पूरा हो जाता है, तो वह बहुत बढ़िया होगा, साफ़ तौर पर गलत साबित हुई। पूरे 19 ज़िला-वार ट्रिब्यूनल कोलकाता में ही होने के कारण, उन गरीब मतदाताओं को — जो पहली नज़र में नागरिक ही थे और जिनकी पहचान हो चुकी थी — अपने रोज़ाना की मज़दूरी छोड़कर दूर-दराज के ज़िलों से इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है।

इस ट्रिब्यूनल प्रक्रिया की भारी विफलता का सबसे बड़ा संकेत कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और एसआईआर अपीलीय ट्रिब्यूनल के सदस्य, जस्टिस टी. एस. शिवज्ञानम ने अपने इस्तीफे के बयान में उजागर किया है। उन्होंने बताया कि 5 से 27 अप्रैल के बीच, दिन-रात पूरी लगन से काम करने के बाद भी, वे कुल 1,777 अपीलों का ही निपटारा कर पाए, जिनमें से 1,717 अपीलों को उन्होंने सही ठहराया। उन्होंने आगे कहा कि ट्रिब्यूनल के सामने दायर की गई 33 लाख अपीलों को पूरा करने में चार साल लग जाएँगे। संयोग से, कांग्रेस के एक नेता को सुप्रीम कोर्ट के सीधे दखल से सुनवाई में प्राथमिकता मिली, उनका नाम मतदाता सूची में फिर से शामिल हो गया, वे चुनाव लड़े और जीत गए।

इसलिए, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अब यह स्पष्ट है कि यह कोई चुनावी पुनरीक्षण नहीं था, एक गहन कवायद होना तो दूर की बात है, बल्कि यह मतदाता सूचियों पर की गई एक 'सर्जिकल स्ट्राइक' थी। इसका निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है : यह मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने का एक सुनियोजित प्रयास था — और इसका सबसे अधिक खामियाज़ा उन मतदाताओं को भुगतना पड़ा, जो सामाजिक और आर्थिक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर थे।

सांप्रदायिक और सामाजिक आयाम

एसआईआर या आईएसआर, जैसा भी आप इसे कहना चाहें — के राज्य के सामाजिक ताने-बाने पर बेहद खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। जहाँ एएसडीडी के तहत 58 लाख नामों को हटाना ज़मीनी हकीकत के करीब लगता है, वहीं यूए श्रेणी की बात बिल्कुल ही अलग है। नामों को हटाने के इस पैटर्न का ज़िलेवार और इलाकेवार जनसंख्या घनत्व की बनावट से मिलान करने पर पता चलता है कि सबसे ज़्यादा नाम उन इलाकों से हटाए गए हैं, जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, और साथ ही उन इलाकों से भी, जहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित@ जनजाति के लोग रहते हैं। इसलिए, यह एक गहरी छाप छोड़ता है कि यह सब एक सोची-समझी योजना के तहत किया गया था, भले ही इसके पीछे कोई दुर्भावना न रही हो।

जिस तरह से एसआईआर की कवायद आयोजित की गई थी, उसका भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया था। इसनेड हिंदुत्व के उस लगातार दावे से मतदाताओं के प्रभावित होने की आशंका पैदा कर दी कि पश्चिम बंगाल 'घुसपैठियों' और 'अवैध प्रवासियों' से भरा हुआ है। लेकिन, वास्तव में, आज के पश्चिम बंगाल में इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। 12 साल पूरे करने के बाद भी, मोदी सरकार के पास इस बात का कोई दस्तावेज़ी सबूत मौजूद नहीं है। ज़ाहिर है, यह मैपिंग की कवायद भी इस बात को साबित नहीं कर सकी और इसीलिए, एक 'अपरिक्षित सॉफ्टवेयर' का इस्तेमाल किया गया और 'तार्किक विसंगति' का एक मनगढ़ंत विचार गढ़ा गया, जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में लोगों को 'यूए' (अनिर्धारित) श्रेणी में डाल दिया गया। भाजपा नेताओं का इस 'बेबस स्थिति' और इसके नतीजों पर लगभग जश्न मनाना — और साथ ही यूए श्रेणी में डाले गए लोगों को यह क्रूर धमकी देना कि उन्हें जल्द ही देश से बाहर निकाल दिया जाएगा — हिंदुत्व की मूल वैचारिक बुनियाद की 'ताकत' का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अहसास है।

स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ₹भारत के गरीबों में इतने सारे मुसलमान क्यों हैं? यह कहना बिल्कुल बकवास है कि उन्हें तलवार के ज़ोर पर धर्म परिवर्तन कराया गया था। उन्होंने ऐसा ज़मींदारों और पुजारियों के ज़ुल्म से आज़ादी पाने के लिए किया था; और इसी का नतीजा है कि बंगाल में खेती-बाड़ी करने वालों में हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ ज़मींदार बहुत ज़्यादा थे। इन गिरे हुए, कुचले हुए करोड़ों लोगों को ऊपर उठाने के बारे में कौन सोचता है? सिर्फ़ कुछ हज़ार ग्रेजुएट मिलकर कोई राष्ट्र नहीं बनाते, न ही कुछ अमीर लोग मिलकर कोई राष्ट्र बनाते हैं। यह सच है कि हमारे पास मौके कम हैं, लेकिन फिर भी 30 करोड़ लोगों को खाना-कपड़ा देने और उन्हें ज़्यादा आरामदायक, बल्कि आलीशान ज़िंदगी देने के लिए हमारे पास काफ़ी संसाधन हैं। हमारी 90 फ़ीसदी आबादी अशिक्षित है — इस बारे में कौन सोचता है? क्या ये 'बाबू लोग' — जिन्हें तथाकथित देशभक्त कहा जाता है— इस बारे में सोचते हैं?₹ [दीवानजी (श्री हरिदास विहारीदास देसाई) को लिखे पत्र से, जैसा कि 'स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण कार्यों' में उद्धृत है।] ऐसा और किसी ने कहा है? इसलिए, अपने घुसपैठिया सिद्धांत को सही ठहराने की जगह, आरएसएस-भाजपा के नेताओं को चाहिए कि वे स्वामीजी के विचारों का और ज़्यादा गहराई से अध्ययन करें और फिर बंगाल के पुनरुद्धार के बारे में बात करें।

असम और 'डी-वोटर' की कवायद

चुनावी जश्न के इस माहौल में, यह बात अब और भी साफ़ होती जा रही है कि एसआईआर की कवायद का मकसद पश्चिम बंगाल पर सिर्फ़ चुनावी नतीजों से कहीं ज़्यादा गहरा असर डालना था। इसका उद्देश्य इस राज्य की पहचान से जुड़ी बुनियाद को फिर से गढ़ना था, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ संघर्षों में सबसे आगे रहा था। बंगाल सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सुधारों की सबसे समृद्ध विरासत का गवाह रहा है। इसलिए, बंगाल के 'नकली पुनरुद्धार' का ढोंग करना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसका 'अग्रदूत' बनाकर पेश करना — जो असल में विभाजन को लागू करवाने वालों में से एक थे — पूरी तरह से बेतुकी कोशिश है। पिछली टीएमसी-नीत सरकार के ख़िलाफ़ लोगों में मौजूद भारी असंतोष (सत्ता-प्रतिकूलता कारक) का फ़ायदा उठाना एक बात है, लेकिन इस प्रगतिशील राज्य को आगे ले जाना बिल्कुल ही दूसरी बात है। समावेशी शासन स्थापित करने की जो नई बातें की जा रही हैं, वे एसआईआर को अपनाने की पृष्ठभूमि में लोगों पर कोई खास असर नहीं डाल पाएंगी; क्योंकि एसआईआर तो अपने आप में एक पूरी तरह से विभाजनकारी कवायद है।

इसके बजाय, भाजपा असम वाली रणनीति अपनाने की कोशिश कर रही है, जहाँ बिना किसी सही जाँच-पड़ताल और असल नागरिकता की बारीकी से जाँच किए बिना ही, बिना दस्तावेज़ वाले मतदाताओं के एक तबके को अवैध ठहराने की कोशिशें की गई। असुरक्षा की भावना को भड़काकर, लोगों के कुछ खास तबकों के लिए 'डी-वोटर' (संदिग्ध मतदाता) की एक श्रेणी तय कर दी गई। इसे एनआरसी की प्रक्रिया और तथाकथित 'डिटेंशन सेंटर' (हिरासत केंद्रों) से जोड़ने की कोशिश की गई; लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बुरी तरह नाकाम होने से ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि भारी-भरकम वित्तीय खर्च के बावजूद, ये दिखावटी सुविधाएँ आज खाली और वीरान जगहों में तब्दील हो चुकी हैं।

यह डिज़ाइन साफ़ है। यू ए श्रेणी के लोगों के भविष्य का फ़ैसला न्यायपालिका द्वारा किए जाने से पहले ही, राज्य सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों के अधिकारों को खत्म करने के संकेत दे रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान जिन महिलाओं के नाम हटा दिए गए हैं, उन्हें राज्य सरकार की 'अन्नपूर्णा भंडार' योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन, हममें से जो लोग एक समावेशी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वे आम जनता के ज़्यादा से ज़्यादा तबकों को एकजुट करके — उनकी जाति, नस्ल और संप्रदाय की परवाह किए बिना और आजीविका के संकट को आधार बनाकर— विभाजन, व्यवधान और तोड़फोड़ की इस रणनीति को हराने के लिए आगे आएंगे। 27 लाख अनिर्णीत लोगों का मुद्दा इस प्रयास का मुख्य केंद्र होगा।

(लेखक माकपा के पोलिट ब्यूरो सदस्य, पूर्व सांसद और 'पीपुल्स डेमोक्रेसी' के संपादक हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं।

डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस अधिकारी: मेहनत से बने या महंगे स्कूलों से पैदा हुए?

● डॉ. विजय गर्ग

आज शिक्षा भी एक बड़े बाजार में बदल चुकी है। कई निजी स्कूल खुद को "भविष्य बनाने वाली फैक्ट्री" की तरह प्रस्तुत करते हैं। उनके विज्ञापनों में दिखाया जाता है: हमारे स्कूल से आईआईटी टॉपर, हमारे स्कूल से नीट चयन, हमारे स्कूल से आईएएस अधिकारी, विदेशों में प्रवेश पाने वाले छात्र, ओलंपियाड विजेता। इन उपलब्धियों को देखकर समाज में यह धारणा बन जाती है कि सफलता का सीधा संबंध महंगी शिक्षा से है।

आज के समय में समाज में एक धारणा तेजी से मजबूत हुई है कि बड़े और महंगे स्कूल ही भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, आईएएस अधिकारी और सफल नागरिक तैयार करते हैं। चमचमाती इमारतें, एयर-कंडीशंड कक्षाएं, स्मार्ट बोर्ड, रोबोटिक्स लैब, अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम, विदेशी यात्राएं, आधुनिक खेल परिसर और लाखों रुपये की फीस देखकर लोगों को लगता है कि सफलता का रास्ता केवल ऐसे ही स्कूलों से होकर गुजरता है।

कई माता-पिता मानते हैं कि यदि उनका बच्चा किसी प्रतिष्ठित और महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसका डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस अधिकारी बनना लगभग तय है। दूसरी ओर, सरकारी या साधारण स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अक्सर कमतर समझा जाता है।

लेकिन क्या वास्तव में सफलता का संबंध केवल महंगे स्कूलों से है?

क्या ऊंची फीस ही ऊंचे सपनों की गारंटी है?

क्या शानदार भवन और आधुनिक सुविधाएं ही महान करियर बनाती हैं?

इन सवालों का उत्तर बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है।

सच्चाई यह है कि डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस अधिकारी केवल महंगे स्कूलों की "उत्पत्ति" नहीं होते। वे बनते हैं —

मेहनत से,
अनुशासन से,
संघर्ष से,
आत्मविश्वास से,
और निरंतर सीखने की इच्छा से।

इतिहास और वर्तमान दोनों इस बात के गवाह हैं कि महान उपलब्धियां केवल अमीर स्कूलों की देन नहीं होतीं।

महंगे स्कूलों की चमक और समाज की सोच

आज शिक्षा भी एक बड़े बाजार में बदल चुकी है। कई निजी स्कूल खुद को "भविष्य बनाने वाली फैक्ट्री" की तरह प्रस्तुत करते हैं। उनके विज्ञापनों में दिखाया जाता है:

हमारे स्कूल से आईआईटी टॉपर,
हमारे स्कूल से नीट चयन,
हमारे स्कूल से आईएएस अधिकारी,
विदेशों में प्रवेश पाने वाले छात्र,
ओलंपियाड विजेता।

इन उपलब्धियों को देखकर समाज में यह धारणा बन जाती है कि सफलता का सीधा संबंध महंगी शिक्षा से है।

इसी कारण:

माता-पिता भारी फीस भरते हैं,
कर्ज लेते हैं,
अपनी जरूरतें कम कर देते हैं,
और बच्चों को बड़े स्कूलों में भेजने की होड़ में लग जाते हैं।

लेकिन अक्सर यह सवाल कोई नहीं पूछता कि: क्या सफलता वास्तव में स्कूल की फीस तय करती है?

स्कूल अवसर दे सकते हैं, सफलता नहीं

यह सच है कि महंगे स्कूलों में कई सुविधाएं होती हैं:

आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं,
डिजिटल शिक्षा,
पुस्तकालय,
करियर काउंसलिंग,
खेल सुविधाएं,
अंग्रेजी वातावरण,
व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम।

ये सुविधाएं बच्चों को बेहतर exposure दे सकती हैं। वे आत्मविश्वास बढ़ा सकती हैं। बच्चों को दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है।

लेकिन सुविधाएं और सफलता दो अलग बातें हैं।

यदि किसी छात्र में:

पढ़ने की आदत नहीं,
लक्ष्य नहीं,
अनुशासन नहीं,
निरंतर अभ्यास नहीं,
तो दुनिया का सबसे महंगा स्कूल भी उसे सफल नहीं बना सकता।

दूसरी ओर, यदि किसी बच्चे में सीखने की भूख है, तो वह साधारण स्कूल से पढ़कर भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है।

भारत की असली तस्वीर

भारत हर साल हजारों ऐसी कहानियां देखता है जहां:

किसान का बेटा डॉक्टर बनता है,
मजदूर की बेटी आईएएस बनती है,
छोटे गांव का छात्र आईआईटी पहुंचता है।

इनमें से कई छात्रों ने:

सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की,
हिंदी या क्षेत्रीय भाषा माध्यम से शिक्षा ली,
सीमित संसाधनों में तैयारी की।
फिर भी वे सफल हुए।
क्यों?
क्योंकि उनके पास था:
संघर्ष,
धैर्य,
आत्मविश्वास,
और मेहनत करने की क्षमता।

कई बार जिन बच्चों के पास कम संसाधन होते हैं, उनमें आगे बढ़ने की भूख ज्यादा होती है। शिक्षा उनके लिए केवल डिग्री नहीं बल्कि जिंदगी बदलने का माध्यम बन जाती है।

डॉक्टर बनने का रास्ता

एक डॉक्टर बनने के लिए केवल बड़ा स्कूल काफी नहीं होता।

इसके लिए चाहिए:

जीव विज्ञान की गहरी समझ,
लगातार अध्ययन,

मानसिक धैर्य,
लंबे समय तक मेहनत,
और आत्मअनुशासन।

नीट जैसी परीक्षा में यह नहीं पूछा जाता कि छात्र किस स्कूल से आया है।

वहां केवल यह देखा जाता है:

ज्ञान कितना है,
प्रश्न हल करने की क्षमता कितनी है,
और तैयारी कितनी मजबूत है।

भारत में हजारों छात्र छोटे कस्बों और गांवों से नीट निकालते हैं। कई छात्र तो बिना महंगी कोचिंग के भी सफलता प्राप्त करते हैं।

इंजीनियर बनने के पीछे क्या जरूरी है?

इंजीनियरिंग केवल किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि:

तार्किक सोच,
समस्या समाधान क्षमता,
गणितीय समझ,
और निरंतर अभ्यास मांगती है।

आईआईटी - जेईई-मेन जैसी परीक्षाएं कठिन इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि वे केवल रटने से पास नहीं होतीं।

आज इंटरनेट और डिजिटल शिक्षा ने शिक्षा की दुनिया बदल दी है।

अब एक छोटे गांव का छात्र भी:

ऑनलाइन लेक्चर,
डिजिटल टेस्ट सीरीज,
युटब
एआई टूल्स,
मुफ्त अध्ययन सामग्री
के माध्यम से तैयारी कर सकता है।

इसलिए अब सफलता केवल बड़े शहरों या महंगे स्कूलों तक सीमित नहीं रही।

आईएएस बनने की असली ताकत

आईएएस अधिकारी बनने के लिए:

व्यापक अध्ययन,
समाज की समझ,
लेखन क्षमता,
धैर्य,
और मानसिक मजबूती की जरूरत होती है।

युपीएससी की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में मानी जाती है।

लेकिन इस परीक्षा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहां:

गांव और शहर,
गरीब और अमीर,
हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम,
सरकारी और निजी स्कूल
सभी एक ही प्रश्नपत्र हल करते हैं।

यह परीक्षा साबित करती है कि असली ताकत दिमाग और मेहनत में होती है, न कि स्कूल की चमक में।

क्या ज्यादा सुविधाएं संघर्ष कम कर देती हैं?

कई बार अत्यधिक आराम बच्चों की संघर्ष क्षमता को कमजोर कर देता है।

जब हर चीज आसानी से मिलती है, तो:

धैर्य कम हो सकता है,
असफलता सहने की क्षमता घट सकती है, मेहनत का महत्व कम महसूस हो सकता है।

दूसरी ओर, संघर्ष में पले बच्चे अक्सर:

ज्यादा मजबूत,
ज्यादा केंद्रित,
और ज्यादा धैर्यवान बनते हैं।
वे असफलता से जल्दी टूटते नहीं हैं।

माता-पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण

किसी भी बच्चे की सफलता में स्कूल से ज्यादा योगदान परिवार का होता है।

यदि घर में:

पढ़ने का माहौल हो,
समय का सम्मान हो,
अनुशासन हो,
प्रेरणा हो,
और सकारात्मक सोच हो,
तो बच्चा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है।

दूसरी ओर, यदि घर में:

अत्यधिक दबाव,
तुलना,
केवल अंकों की दौड़,
और मानसिक तनाव हो,
तो महंगा स्कूल भी बच्चे को खुश या सफल नहीं बना सकता।

क्या केवल करियर ही सफलता है?

समाज अक्सर सफलता को केवल:

डॉक्टर,
इंजीनियर,
आईएएस,
या बड़ी नौकरी
से जोड़ देता है।

लेकिन असली सफलता केवल पद या वेतन नहीं होती।

सच्ची सफलता है:

अच्छा इंसान बनना,
समाज के लिए उपयोगी होना,
ईमानदार रहना,
और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग करना।

शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है।

शिक्षा में बढ़ती असमानता

आज भारत में शिक्षा के क्षेत्र में गहरी असमानता दिखाई देती है।

एक तरफ:
लाखों रुपये फीस वाले स्कूल हैं,
दूसरी तरफ:
ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं।

यह अंतर केवल शिक्षा का नहीं बल्कि अवसरों का भी है।

फिर भी, इतिहास बताता है कि प्रतिभा सुविधाओं की मोहताज नहीं होती।

छोटे स्कूलों से भी बड़े सपने निकल सकते है

असली "सफलता की फैक्ट्री" क्या है?

यदि सच पूछा जाए तो सफलता की सबसे बड़ी फैक्ट्री कोई महंगा स्कूल नहीं बल्कि:

मेहनत,
अनुशासन,
आत्मविश्वास,
निरंतर अभ्यास,
और सीखने की भूख है।

महंगे स्कूल अवसर दे सकते हैं। वे exposure दे सकते हैं। वे आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं।

लेकिन वे सफलता खरीद नहीं सकते।

नई शिक्षा व्यवस्था और बदलती दुनिया

आज दुनिया तेजी से बदल रही है।

अब केवल डिग्री नहीं बल्कि:

कौशल,
रचनात्मकता,
समस्या समाधान क्षमता,
और भावनात्मक बुद्धिमत्ता
भी महत्वपूर्ण हो गई हैं।

भविष्य में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो:

लगातार सीखते रहेंगे,
नई तकनीकों को अपनाएंगे,
और मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे।

यह गुण किसी भी स्कूल में विकसित हो सकते हैं — चाहे वह महंगा हो या साधारण।

निष्कर्ष

डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस अधिकारी केवल महंगे स्कूलों से पैदा नहीं होते।

वे बनते हैं:

सपनों से,
संघर्ष से,
अनुशासन से,
किताबों से,
असफलताओं से,
और निरंतर मेहनत से।

महंगे स्कूल सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन वे किसी बच्चे की सफलता की गारंटी नहीं बन सकते।

एक छोटे गांव का बच्चा भी IAS बन सकता है। सरकारी स्कूल का छात्र भी डॉक्टर बन सकता है। साधारण परिवार का बच्चा भी महान इंजीनियर बन सकता है।

क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो:

परिस्थितियों से लड़ता है,
हार के बाद फिर उठता है,
और अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करता है।

सफलता की असली कीमत फीस नहीं होती।

उसकी असली कीमत होती है — मेहनत, धैर्य और लगन।

डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

नीट परीक्षा रद्द होने पर आपके बच्चे का दर्द कौन समझ रहा है

डॉ विजय गर्ग

भारत में चिकित्सा शिक्षा केवल एक डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के सपनों, संघर्षों और वर्षों की मेहनत का प्रतीक है। हर साल लाखों विद्यार्थी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट की तैयारी करते हैं। कोई छात्र गाँव के छोटे से कमरे में बैठकर पढ़ता है, कोई शहर की कोचिंग में दिन-रात मेहनत करता है, कोई आर्थिक तंगी के बावजूद किताबें खरीदता है, तो कोई अपने माता-पिता के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी किशोरावस्था तक त्याग देता है।

लेकिन जब परीक्षा रद्द होने, पेपर लीक होने, अनियमितताओं या पुनर्परीक्षा जैसी खबरें आती हैं, तब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है—आख़िर उन बच्चों का दर्द कौन समझ रहा है जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया इस परीक्षा के इर्द-गिर्द बना ली थी?

केवल परीक्षा नहीं, वर्षों की तपस्या

नीट की तैयारी सामान्य परीक्षा की तैयारी नहीं होती। यह मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संघर्ष का लंबा सफर है। कई विद्यार्थी दसवीं कक्षा से ही अपने जीवन को सीमित कर देते हैं। मोबाइल कम, घूमना कम, त्योहारों से दूरी, रिश्तेदारों से दूरी, खेल-कूद तक छोड़ देना—ये सब केवल एक लक्ष्य के लिए होता है।

जब परीक्षा अचानक रद्द हो जाए या विवादों में घिर जाए, तब केवल एक तारीख नहीं बदलती, बल्कि लाखों बच्चों का मानसिक संतुलन हिल जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का सम्मान नहीं हुआ। जिन रातों की नींद उन्होंने छोड़ी, जिन इच्छाओं को दबाया, जिन सपनों को संजोया—सब कुछ अनिश्चितता में बदल गया।

बच्चों की चुप्पी को समझना होगा

अक्सर माता-पिता और समाज केवल इतना कहते हैं—"फिर से तैयारी कर लो", "अभी उम्र पड़ी है", "एक परीक्षा ही तो है"। लेकिन क्या वास्तव में यह केवल एक परीक्षा है?

जिस छात्र ने प्रतिदिन 12–14 घंटे पढ़ाई की हो, जिसने लगातार दबाव झेला हो, जिसने दोस्तों से दूरी बना ली हो, जिसके जीवन का हर निर्णय नीट के इर्द-गिर्द घूमता हो, उसके लिए परीक्षा रद्द होना गहरे भावनात्मक आघात जैसा हो सकता है।

कई बच्चे बाहर से शांत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से टूट जाते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ। कुछ को डर सताने लगता है कि उनका भविष्य अस्थिर हो गया है। कुछ बच्चे आत्मविश्वास खो बैठते हैं। कई छात्र यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि दोबारा वही मानसिक तैयारी कैसे करेंगे।

सबसे अधिक दबाव मध्यमवर्ग और ग्रामीण विद्यार्थियों पर

भारत का मध्यमवर्गीय परिवार अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा देता है। कई परिवार कोचिंग फीस भरने के लिए कर्ज लेते हैं। किसान परिवार अपनी जमीन तक गिरवी रख देते हैं। मजदूर माता-पिता अतिरिक्त काम करते हैं ताकि बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो।

ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी तो और अधिक संघर्ष करते हैं। उनके पास न महंगी कोचिंग होती है, न अत्याधुनिक संसाधन। फिर भी वे मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का सपना देखते हैं। जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, तब इन्हीं छात्रों को सबसे अधिक निराशा होती है, क्योंकि उनके पास बार-बार अवसर लेने की आर्थिक क्षमता नहीं होती।

मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी

हमारे समाज में अभी भी विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लिया जाता। परीक्षा रद्द होने या अनिश्चितता की स्थिति में बच्चों में तनाव, चिंता, अनिद्रा, निराशा और भय बढ़ सकता है। लेकिन अधिकतर लोग केवल परिणाम की बात करते हैं, बच्चे की मानसिक स्थिति की नहीं।

कई विद्यार्थी अपने दर्द को व्यक्त भी नहीं कर पाते। वे अपने माता-पिता को परेशान नहीं करना चाहते। वे चुप रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। यही चुप्पी सबसे खतरनाक होती है।

बच्चों को इस समय केवल सलाह नहीं, बल्कि संवेदनशील संवाद की आवश्यकता होती है। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि उनका मूल्य केवल एक परीक्षा के परिणाम से तय नहीं होता।

शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा क्यों जरूरी है?

किसी भी देश की परीक्षा प्रणाली केवल अंक देने का माध्यम नहीं होती; वह युवाओं के विश्वास की नींव होती है। यदि बार-बार पेपर लीक, परीक्षा रद्द, अनियमितता या पारदर्शिता पर प्रश्न उठेंगे, तो

विद्यार्थियों का विश्वास कमजोर होगा।

एक छात्र को यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी मेहनत ईमानदारी से आंकी जाएगी। यदि मेहनती छात्र को लगे कि व्यवस्था निष्पक्ष नहीं है, तो उसके भीतर निराशा पैदा होना स्वाभाविक है।

इसलिए परीक्षा प्रणाली को केवल तकनीकी रूप से मजबूत बनाना पर्याप्त नहीं है। उसे नैतिक रूप से भी विश्वसनीय बनाना होगा।

माता-पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण

ऐसे समय में बच्चों को डांटने, तुलना करने या लगातार पढ़ाई के लिए दबाव बनाने की बजाय उनके साथ बैठना अधिक आवश्यक है। माता-पिता यदि केवल इतना कह दें—"हम तुम्हारे साथ हैं"—तो बच्चे का आधा तनाव कम हो सकता है।

उन्हें यह समझना चाहिए कि बच्चा मशीन नहीं है। वह भावनाओं वाला इंसान है। उसकी थकान, डर और असुरक्षा वास्तविक हैं। बच्चों को बार-बार यह महसूस कराना जरूरी है कि जीवन केवल नीट तक सीमित नहीं है।

समाज को भी बदलनी होगी सोच

हमारे समाज में डॉक्टर बनना प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि नीट जैसी परीक्षाओं का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर बच्चा अलग है और सफलता के रास्ते भी अलग-अलग होते हैं।

> *हमारे समाज में अभी भी विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लिया जाता। परीक्षा रद्द होने या अनिश्चितता की स्थिति में बच्चों में तनाव, चिंता, अनिद्रा, निराशा और भय बढ़ सकता है। लेकिन अधिकतर लोग केवल परिणाम की बात करते हैं, बच्चे की मानसिक स्थिति की नहीं।*

यदि किसी बच्चे का एक प्रयास प्रभावित हो गया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका जीवन समाप्त हो गया। देश को अच्छे शिक्षक, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, लेखक, इंजीनियर, उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता भी चाहिए।

बच्चों की पहचान केवल एक प्रवेश परीक्षा से नहीं होनी चाहिए।

सरकार और संस्थाओं की जिम्मेदारी

जब भी परीक्षा संबंधी विवाद सामने आते हैं, तब केवल प्रशासनिक बयान पर्याप्त नहीं होते। विद्यार्थियों और अभिभावकों को स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध जानकारी मिलनी चाहिए। अनिश्चितता जितनी लंबी होगी, तनाव उतना बढ़ेगा।

साथ ही दोषियों पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है, ताकि मेहनती छात्रों का विश्वास कायम रह सके। परीक्षा की सुरक्षा केवल तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का प्रश्न है।

बच्चों को क्या समझना चाहिए?

जो विद्यार्थी इस समय निराश हैं, उन्हें यह समझना जरूरी है कि उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। मेहनत कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होती। ज्ञान, अनुशासन और धैर्य जीवन भर साथ रहते हैं।

एक परीक्षा की परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन जीवन के अवसर केवल एक रास्ते तक सीमित नहीं होते। कठिन समय व्यक्ति को और मजबूत भी बनाता है।

निष्कर्ष

नीट परीक्षा रद्द होने की खबरें केवल प्रशासनिक घटनाएँ नहीं हैं। इनके पीछे लाखों बच्चों की भावनाएँ, परिवारों की उम्मीदें और वर्षों का संघर्ष छिपा होता है। इसलिए जब हम परीक्षा विवादों पर चर्चा करें, तो आंकड़ों से पहले उन चेहरों को याद करें जो रातों की नींद छोड़कर अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहे थे।

सबसे बड़ा प्रश्न यही है—क्या हम केवल परीक्षा व्यवस्था सुधारने की बात करेंगे, या उन बच्चों के टूटते मन को भी समझने की कोशिश करेंगे?

क्योंकि कभी-कभी बच्चों को सबसे अधिक आवश्यकता किसी समाधान से नहीं, बल्कि इस एहसास से होती है कि उनकी मेहनत और उनका दर्द वास्तव में देखा और समझा जा रहा है।

डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

ओडिशा के राउरकेला के लिए ए टी आर -72 विमान सेवा बहाल करने की मांग तेज

सूत्रों के अनुसार, हवाईअड्डा विस्तार योजना के तहत राउरकेला एयरपोर्ट का पूर्ण स्वामित्व सेल से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है।

राउरकेला : राउरकेला हवाईअड्डे के विस्तार में अभी कई वर्ष लगने की संभावना के बीच राउरकेला-भुवनेश्वर और राउरकेला-कोलकाता मार्ग पर ए टी आर -72 विमान सेवा बहाल करने की मांग तेज हो गई है, ताकि बढ़ती हवाई यात्रियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

वर्तमान में इस मार्ग पर केवल नौ-सीटर विमान संचालित हो रहा है, जो बढ़ती यात्री संख्या के लिए अपर्याप्त साबित हो रहा है।

राय ने उन्हें बताया कि वे इस समस्या से पहले से अवगत हैं और अंतरिम व्यवस्था के रूप में 72-सीटर विमान सेवा शुरू कराने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।

राउरकेला गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ राजकुमार यादव ने कहा कि एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किनजारपू राम मोहन नायडू से ए टी आर -72 सेवा तत्काल बहाल करने की मांग की है, ताकि यात्रियों को हो रही परेशानी दूर हो सके।

राउरकेला स्टील प्लांट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि संयंत्र की उत्पादन क्षमता को दोगुने से अधिक बढ़ाने के लिए 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की योजना पर काम शुरू हो चुका है। ऐसे में बेहतर हवाई संपर्क की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान नौ-सीटर विमान सेवा बेहद अपर्याप्त है।

10 जनवरी को राउरकेला के पास सेसना 208 कैरावान विमान की आपात लैंडिंग की घटना ने यात्रियों का भरोसा भी प्रभावित किया है। इसके बाद कई यात्री छोटे विमानों में यात्रा करने से हिचकिचा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि अलायंस एयर ने जुलाई 2025 के मध्य में आर सि एस -उड़ान योजना के तहत राउरकेला-भुवनेश्वर और राउरकेला-कोलकाता मार्ग पर ए टी आर -72 सेवा शुरू की थी। हालांकि सीटों की अच्छी बुकिंग के बावजूद एयरलाइन ने ए टी आर -72 विमानों की सीमित उपलब्धता का हवाला देते हुए सेवा बंद कर दी। इसके बाद 5 दिसंबर 2025 से इंडिया वन एयर अस्थायी रूप से राउरकेला-भुवनेश्वर मार्ग पर नौ-सीटर विमान का संचालन कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, एयरपोर्ट विस्तार योजना के तहत राउरकेला एयरपोर्ट का पूर्ण स्वामित्व सेल से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जारी है। ओडिशा सरकार इस एयरपोर्ट को कोड- फॉर सि श्रेणी में विकसित करने की योजना बना रही है, जिससे बड़े विमानों का संचालन संभव हो सकेगा।

झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवनों का नियमितीकरण नियमावली लागू

मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया अनावरण,तीन किस्तों में नियमित करण हेतु राशि लेगी सरकार

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन से झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली,2026 के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया ।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है जहाँ राज्य की जनता को एक मौक़ा प्रदान किया जा रहा है कि वे अनाधिकृत तरीक़े से बने अपने मकानों का नियमितीकरण करा सकेंगे । जो लोग चिंतित थे कि उनके अनियमित मकानों का क्या होगा सरकार इस दिशा में राहत देते हुए भवन नियमितीकरण योजना ले कर आई है । अब लोग पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर अपना मकान नियमित करा सकेंगे।

सुदिव्य कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की प्रबल इच्छाशक्ति थी कि राज्य के लोगों को राहत देते हुए अनियमित मकानों को नियमितीकरण करने का एक मौक़ा जरूर दिया जाना चाहिए । इसी के मद्देनजर नगर विकास विभाग ने बड़े कठिन और अथक प्रयासों के बाद यह योजना तैयार हुई है और अब ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ हो गया है।

मंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों का अनुपालन में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भवन नियमितीकरण का उद्देश्य अनियमितीकरण को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि जो लोग बिना नक्शा और मास्टर प्लान के अपना मकान बना लिए है ये उन लोगों के लिए एक मौक़ा है। सरकार ने नियमितीकरण नियमावली को बहुत ही सरल और लिबरल बनाया है और नियमित करने में लगने वाली राशि को भी तीन किस्तों में भुगतान का प्रावधान कर लोगों को राहत देने का काम किया है ।

प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि सरकार नगरीय क्षेत्रों के विकास को गंभीरता से ले रही है । शहर की सूरत बदल रही है । इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है । रांची में 3 फ्लाइओवर बन कर तैयार हैं, सिरमटोली कनेक्टिंग फ्लाइओवर भी ऑनगोइंग है । अरगोड़ा , करमटोली और हरमू 3 नए फ्लाइओवर की स्वीकृति मिल चुकी है। जमशेदपुर और धनबाद में भी फ्लाईओवर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का निदेश है कि शहरीकरण अव्यवस्थित ढंग से ना हो। रोड ,फुटपाथ , टाउनहॉल, नाली सभी व्यवस्थित हों। शहरों में उन्नत बस स्टैंड हो। इस दिशा में काम जारी है।

म्युनिसिपल के रेवन्यू बढ़ाने पर भी फोकस है । मानव संसाधन पर भी ज़ोर दिया जा रहा है । टाउन प्लानर , इंजीनियर आदि की नियुक्ति सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि भवन नियमितीकरण नियमावली 2026 को हम योजना कह सकते हैं । इससे लोगों को एक बार मौका दिया जा रहा है कि वे अपने मकानों को नियमित करा सकेंगे। उन्होंने इसकी प्रक्रिया की जानकारी दी। कहा कि इसके शुभारंभ से लेकर 2 माह के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना है और 6 माह के अंदर नियमितीकरण का निर्णय लिया जा सकेगा ।साथ ही G+2 और 300 वर्गमीटर से कम में बने मकानों का ही नियमितीकरण होगा । सूरज कुमार डायरेक्टर सूडा ने कहा कि भवन नियमितीकरण नियमावली -2026 सरकार का ऐतिहासिक कदम है । किसी कारण से लोगों ने अपने मकान को बिना नक्शा पास कराए बना लिया है ,ऐसे अनाधिकृत रूप से बने भवन का नियमतीकरण का निर्णय सरकार ने लिया है ताकि झारखंड के नागरिकों को राहत पहुंचाई जाय ।भवन नियमितीकरण योजना का लाभ सभी लोग उठायें । झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली,2026 का लाभ लेने के लिए पोर्टल का शुभारंभ हो गया है । इस पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन करें । आवेदन के लिए 2माह का समय है। इस अवसर पर पोर्टल पर किस प्रकार आवेदन करना है इसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन निदेशक सूडा सूरज कुमार ने मंत्री के समक्ष किया । इस अवसर पर नगर विकास विभाग के विशेष सचिव ज्ञानेंद्र कुमार , अपर सचिव जुल्फिकार अली , धनबाद नगर आयुक्त आशीष सहित नगर विकास एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण के पदाधिकारीगण और फिक्की के पदाधिकारी उपस्थित थे ।

सादगी से सशक्त राष्ट्र की ओर...

डॉ. शैलेश शुक्ला

भारत एक विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ सरकार का प्रत्येक निर्णय करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। सरकार जनता के कर से चलती है और इसलिए सरकारी धन का प्रत्येक रुपया जनता की मेहनत, पसीने और विश्वास का प्रतीक होता है। जब देश का सामान्य नागरिक बढ़ती महँगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं से संघर्ष कर रहा हो, तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या सरकारों और प्रशासनिक तंत्र को भी अपने खर्चों में सादगी और संयम नहीं अपनाना चाहिए? लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जनता के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता का भी नाम है। यदि देश का आम नागरिक सीमित आय में अपना घर चलाने के लिए अनेक प्रकार की कटौतियाँ करता है, तो सरकारों को भी राष्ट्रहित में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण लगाने की नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी तंत्र में सादगी को केवल भाषणों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे व्यवहार और नीति का स्थायी हिस्सा बनाया जाए।

पिछले कुछ वर्षों में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि सरकारी आयोजनों, प्रचार अभियानों, विशाल रैलियों, विदेशी दौरों, भव्य स्वागत समारोहों और अत्यधिक सुरक्षा व्यवस्थाओं पर अरबों रुपये खर्च किए जाते हैं। कई बार ये खर्च ऐसे समय में भी होते हैं जब देश के अनेक हिस्सों में किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे होते हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहे होते हैं और सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव दिखाई देता है। जनता यह देखकर स्वाभाविक रूप से प्रश्न करती है कि क्या इन खर्चों में कुछ संयम नहीं बरता जा सकता? क्या लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए सादगी पर्याप्त नहीं है? यदि सरकारी कार्यक्रमों में अत्यधिक दिखावा कम कर दिया जाए, महंगे मंचों और सजावटों की जगह सरल आयोजन किए जाएँ, तो इससे न केवल सरकारी धन की बचत होगी बल्कि जनता के बीच यह संदेश भी जाएगा कि सरकार स्वयं भी त्याग और अनुशासन का पालन कर रही है।

भारतीय समाज में सादगी और मितव्ययिता की परंपरा सदियों पुरानी रही है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक नेताओं ने अत्यंत साधारण जीवन जीते हुए भी महान कार्य किए। उन्होंने यह सिद्ध किया कि राष्ट्र निर्माण के लिए वैभव नहीं, बल्कि विचार, ईमानदारी और सेवा भावना आवश्यक होती है। आज दुर्भाग्य से राजनीति और प्रशासन के कई क्षेत्रों में दिखावे की संस्कृति बढ़ती दिखाई देती है। बड़े-बड़े काफिले, महंगे होटल, विशेष विमानों का उपयोग, अत्यधिक प्रचार और स्वागत-सम्मान की परंपराएँ आम जनता और शासक वर्ग के बीच दूरी पैदा करती हैं। लोकतंत्र में शासक और जनता के बीच यह दूरी जितनी कम होगी, शासन उतना ही अधिक संवेदनशील और प्रभावी होगा। इसलिए समय की माँग है कि सादगी को फिर से राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा बनाया जाए।

सरकारी खर्चों में बचत का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि बचाया गया धन शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सिंचाई, रोजगार और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा। आज भी देश के अनेक सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, कई अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों की कमी है तथा गाँवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यदि सरकारें प्रचार और दिखावे पर होने वाले खर्च का एक हिस्सा भी इन क्षेत्रों में लगा दें, तो करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। यह समझना आवश्यक है कि राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादक क्षमता में होती है, न कि सरकारी आयोजनों की भव्यता में।

डिजिटल तकनीक के इस युग में अनेक सरकारी कार्य अत्यंत कम लागत में किए जा सकते हैं। बैठकों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित कर यात्रा और आवास पर होने वाले बड़े खर्च को कम किया जा सकता है। सरकारी फाइलों को पूर्णतः डिजिटल बनाने से कागज, प्रिंटिंग और भंडारण पर होने वाला खर्च घटेगा। इसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाएँ तो बिजली पर होने वाला खर्च भी कम किया जा सकता है। सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग केवल पर्यावरण संरक्षण ही नहीं करेगा, बल्कि दीर्घकाल में सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश में करोड़ों लोग बिजली और पानी बचाने का प्रयास करते हैं, उसी देश के अनेक सरकारी कार्यालयों में संसाधनों की भारी बर्बादी दिखाई देती है।

सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में पारदर्शिता की कमी भी अनावश्यक खर्च का एक बड़ा कारण है। कई परियोजनाएँ वर्षों तक अधूरी पड़ी रहती हैं, उनकी लागत कई गुना बढ़ जाती है और अंततः उसका बोझ जनता पर पड़ता है। यदि समयबद्ध निगरानी, तकनीकी पारदर्शिता और सामाजिक लेखा परीक्षण की व्यवस्था मजबूत हो, तो भ्रष्टाचार और अपव्यय दोनों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। जनता यह जानना चाहती है कि उसके द्वारा दिए गए कर का उपयोग कहाँ और कैसे हो रहा है। इसलिए सभी मंत्रालयों और विभागों के खर्च का नियमित सार्वजनिक विवरण जारी किया जाना चाहिए। जब जनता को पारदर्शिता दिखाई देगी, तब सरकार पर विश्वास भी मजबूत होगा।

यह भी आवश्यक है कि जनप्रतिनिधि स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करें। यदि सांसद, विधायक और मंत्री सादगी अपनाएँ, अनावश्यक सुविधाओं का त्याग करें और सार्वजनिक जीवन में संयम का संदेश दें, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा। समाज में नैतिक नेतृत्व का महत्व बहुत बड़ा होता है। जब जनता अपने नेताओं को सादगी और अनुशासन का पालन करते हुए देखेगी, तब वह भी राष्ट्रहित में त्याग और सहयोग के लिए प्रेरित होगी। इसके विपरीत यदि जनता को यह लगे कि सरकार केवल जनता से बचत की अपेक्षा करती है जबकि स्वयं अपव्यय में लगी हुई है, तो लोकतांत्रिक विश्वास कमजोर होता जाएगा।

आज विश्व के अनेक देशों में शासन व्यवस्था को अधिक किफायती और उत्तरदायी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई देशों ने सरकारी खर्चों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया है, जिससे भ्रष्टाचार और फिजूलखर्ची पर नियंत्रण पाया जा सका है। भारत जैसे विशाल देश में भी यह परिवर्तन संभव है, बशर्ते राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत हो। सरकार यदि चाहे तो कुछ वर्षों के भीतर ही सरकारी खर्चों में हजारों करोड़ रुपये की बचत कर सकती है। यह बचत देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ विकास परियोजनाओं को गति देने में भी सहायक होगी।

यह समझना चाहिए कि सादगी का अर्थ विकास विरोध नहीं है। सादगी का अर्थ केवल इतना है कि सार्वजनिक धन का उपयोग विवेकपूर्ण, जिम्मेदार और राष्ट्रहित में किया जाए। जहाँ खर्च आवश्यक हो, वहाँ अवश्य हो; लेकिन जहाँ केवल दिखावे और प्रचार के लिए खर्च किया जा रहा हो, वहाँ संयम अपनाना ही उचित है। लोकतंत्र में सरकार जनता की सेवक होती है, स्वामी नहीं। इसलिए सरकारी खर्चों की प्राथमिकता भी जनता की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार तय होनी चाहिए।

संकल्प लें 'विकसित भारत के निर्माण में हमारी भूमिका क्या हो

डॉ मुश्ताक़ अहमद शाह सहज़

किसी भी राष्ट्र की नियति केवल उसकी सीमाओं या सरकारी नीतियों से तय नहीं होती, बल्कि उसके नागरिकों के सामूहिक संकल्प और पुरुषार्थ से परिभाषित होती है। आज जब हम 'विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो यह केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण का आह्वान है। प्रश्न यह नहीं है कि भारत विकसित बनेगा या नहीं, प्रश्न यह है कि उस विकास की यात्रा में हमारी व्यक्तिगत आहुति क्या होगी?

विकास के स्तंभ, नीतिगत और संरचनात्मक प्रयास,

भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें बहुआयामी मोर्चों पर युद्धस्तर पर काम करना होगा। इसके मुख्य स्तंभ हैं,नवाचार और तकनीकी नेतृत्व जहाँ अब हम केवल 'अनुकरण' करने वाले देश नहीं रह सकते, हमें 'नूतन अन्वेषण' (इनोवेशनिन) के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करना होगा। 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस) अंतरिक्ष विज्ञान और 'नवीकरणीय ऊर्जा' (ग्रीन ईनर्जी) जैसे क्षेत्रों में निवेश और शोध हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षा और कौशल विकास हमारी विशाल जनसंख्या हमारी सबसे बड़ी पूंजी है बशर्ते वह कुशल हो। नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ 'व्यावसायिक प्रशिक्षण' को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलानी होगी।

बुनियादी ढांचे का कायाकल्प 'गतिशक्ति' जैसी योजनाएं परिवहन और 'तार्किक प्रबंधन' की लागत घटाने में मील का पत्थर हैं। आधुनिक बंदरगाह, 'द्रुतमार्ग' और 'अंकीय आधारभूत संरचना' ही आर्थिक क्रांति की रीढ़ बनेंगे। सामाजिक समावेश विकास तब तक अधूरा है जब तक उसका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक न पहुंचे। स्वास्थ्य, पोषण और लैंगिक समानता' के बिना 'विकसित भारत' की कल्पना बेमानी है।

क्या हम भी निभा सकते हैं अहम भूमिका?

अक्सर हम सोचते हैं कि राष्ट्र निर्माण केवल राजनेताओं, वैज्ञानिकों या उद्योगपतियों का काम है। लेकिन हकीकत यह है कि एक विकसित राष्ट्र, विकसित नागरिकों का समूह होता है। एक आम नागरिक के रूप में हमारी भूमिका निर्णायक है,कर्तव्य-बोध का जागरण हम अधिकारों की बात तो मुखर होकर करते हैं लेकिन कर्तव्यों पर मौन साध लेते हैं। 'कर' की ईमानदारी से अदायगी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और कानून का पालन करना विकास की पहली शर्त है। स्थानीय का सम्मान, जब हम स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं तो हम सीधे तौर पर अपने देश के लघु उद्योगों और कारीगरों को सशक्त बना रहे होते हैं। आर्थिक स्वावलंबन की शुरुआत हमारे ख़रीदारी के निर्णयों से होती है। सतत जीवनशैली, विकसित भारत का अर्थ केवल सिमेंट-कंक्रीट के निर्जीव ढांचों'का समूह नहीं है; जल संरक्षण, ऊर्जा की बचत और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हमारी नागरिक जिम्मेदारी है। अंकीय और सामाजिक साक्षरता' सूचना के इस युग में भ्रामक ख़बरों को रोकना और तकनीक का सही उपयोग करना भी राष्ट्र सेवा का ही एक रूप है।

उद्धरण की गहराई,,,संचिकाएं बनाम ज़मीनी हक़ीक़त

₹राष्ट्र निर्माण का कार्य केवल सरकारी संचिकाओं (फ़ाइलों) में नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ नागरिकों के दिलों और उनके कर्मों में संपन्न होता है।₹ यह वाक्य मात्र एक सुविचार नहीं बल्कि नागरिक चेतना का वह मंत्र है जो किसी भी विकासशील देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने की शक्ति रखता है। इसके पीछे के दर्शन को समझें,,संचिकाएं बनाम ज़मीनी हक़ीक़त सरकारी संचिकाएं नीति निर्माण' का प्रतीक हैं। वे राह दिखाती हैं, धन आवंटित करती हैं और योजनाएं बनाती हैं, लेकिन कोई भी संचिका खुद चलकर सड़क नहीं बना सकती, न ही वह किसी कुपोषित बच्चे का पेट भर सकती है। संचिकाएं केवल 'इच्छाशक्ति' का लिखित दस्तावेज हैं जबकि नागरिकों के कर्म उस इच्छाशक्ति का 'साक्षात प्रकटीकरण'हैं। जब एक 'अभियंता' ईमानदारी से पुल बनाता है या एक सफ़ाईकर्मी अपना कर्तव्य समझकर कचरा उठाता है, तब वह संचिका हकीकत में बदलती है।

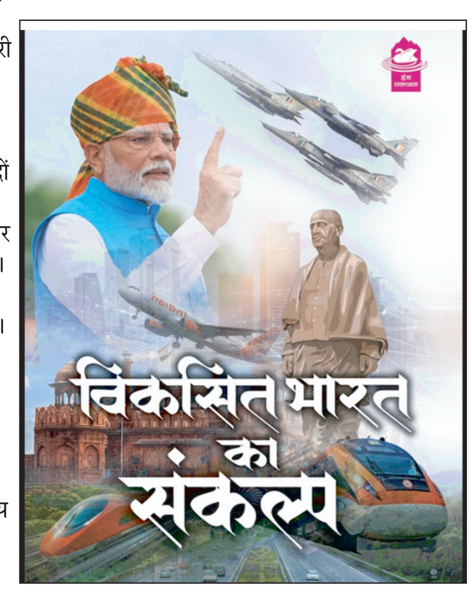

'दिलों' में संकल्प की भूमिका, जब तक राष्ट्र के प्रति प्रेम और ज़िम्मेदारी का भाव नागरिकों के हृदय में नहीं होगा, तब तक कोई भी कानून प्रभावी नहीं हो सकता। नैतिकता से भ्रष्टाचार फ़ाइलें बंद करने से नहीं, बल्कि नागरिक के 'हृदय' में ईमानदारी के उदय से ख़त्म होगा। एकजुटता से जब देश के 140 करोड़ लोग दिल से यह महसूस करते हैं कि देश की संपत्ति उनकी अपनी है, तब सार्वजनिक तोड़-फोड़ और हिंसा का अंत होता है। 'कर्मों' की शक्ति, राष्ट्र निर्माण छोटे-छोटे रोजमर्रा के कामों का योग है एक छात्र के रूप में पूरी निष्ठा से पढ़ाई करना ताकि भविष्य में देश को एक विशेषज्ञ मिले, एक 'उद्यमी' के रूप में रोजगार के अवसर पैदा करना और भारत में निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर ले जाना।

भारत को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य केवल सरकारी आंकड़ों का खेल नहीं है, इसमें जन-भागीदारी' सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा में सरकारी भूमिका विद्यालय बनाना और बजट देना है, जबकि नागरिक का काम सीखना, नवाचार करना और साक्षरता फैलाना है। स्वच्छता में सरकार का काम कूड़ेदान लगाना और अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र' बनाना है, जबकि नागरिक का काम कचरा न फैलाना और गीला-सूखा कचरा अलग करना है। अर्थव्यवस्था में सरकारी नीतियाँ बनाना और ब्याज दरें तय करना है, जबकि नागरिक का काम स्वदेशी अपनाना, निवेश करना और कौशल सीखना है।

विकसित भारत का मार्ग चुनौतियों से भरा है लेकिन असंभव नहीं। 'सकल घरेलू उत्पाद' के आंकड़ों और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ-साथ हमें अपनी कार्य-संस्कृति में भी बदलाव लाना होगा। हमें 'चलता है' वाली मानसिकता को त्यागकर उत्कृष्टता' को अपनाना होगा। जब एक किसान अपनी उपज बढ़ाने के लिए नई तकनीक अपनाता है, जब एक शिक्षक पूरी निष्ठा से भविष्य की पीढ़ी गढ़ता है और जब एक युवा 'नवाचारी लघु उद्योग' के जरिए रोजगार सृजन करता है, तो वह 'विकसित भारत' की नींव रख रहा होता है।

यह समय उदासीनता का नहीं उत्साह का है। आइए हम सब मिलकर इस महायज्ञ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। संक्षेप में, सरकार केवल एक'संचालक' की तरह है, लेकिन असली संगीत 'वाद्ययंत्र' बजाने वाले नागरिकों के सामूहिक प्रयास से निकलता है। जब हर व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का संकल्प लेता है, तभी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव होता है।

पंजाब सरकार द्वारा भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर लगभग 17.72 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों की शुरुआत

राज्यसभा सदस्य बलबीर सिंह सीचेवाल, कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और चेयरमैन श्री बाल जोगी ने विकास कार्यों का शुभारंभ किया
पावन वाल्मीकि स्थान के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी – संत सीचेवाल
अक्टूबर 2026 में भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस बड़े स्तर पर मनाया जाएगा – हरभजन सिंह ईटीओ
वाल्मीकि स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी – बाल जोगी प्रगट नाथ

अमृतसर, 14 मई (साहिल बेरी) —

मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल के विकास के लिए 17 करोड़ 72 लाख रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों की आज शुरुआत की गई। इन विकास कार्यों का उद्घाटन राज्यसभा सदस्य एवं पर्यावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सीचेवाल, राज्य के लोक निर्माण मंत्री श्री हरभजन सिंह ईटीओ तथा भगवान वाल्मीकि जी तीर्थ स्थल श्राइन बोर्ड के एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन श्री बाल जोगी प्रगट नाथ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

इस अवसर पर विकास कार्यों की शुरुआत करते हुए संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने कहा कि इस पावन स्थान के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि भगवान वाल्मीकि जी द्वारा दिखाए गए प्रेम, त्याग और गरीबों की सेवा के मार्ग को अपनाकर एक बेहतर समाज का निर्माण करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आदिकवि भगवान वाल्मीकि जी की अमर रचना महान महाकाव्य रामायण सदैव मानवता को सत्य का मार्ग दिखाती रहेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली यह पहली सरकार है जो वंचित वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के तीर्थ स्थल के विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है।

इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री श्री हरभजन सिंह ईटीओ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा भगवान वाल्मीकि जी तीर्थ स्थल के विकास के लिए 17.72 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लगभग 2.8 करोड़ रुपये की लागत से मुख्य मंदिर की पेंटिंग/पॉलिशिंग, मंदिर तक जाने वाले रास्ते के पिलरों की मरम्मत तथा सैंडस्टोन की सिलिकॉन कटिंग का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा 3.74 करोड़ रुपये की लागत से पवित्र सरोवर की सफाई, जिसमें गाद निकालना, साफ रेत डालना आदि कार्य शामिल हैं।

उन्होंने आगे बताया कि 2.42 करोड़ रुपये की लागत से संगत हॉल, लंगर हॉल, सराय और पैनोरमा हॉल की मरम्मत और पेंटिंग का कार्य किया जाएगा। लगभग 1.74 करोड़ रुपये की लागत से श्रद्धालुओं के लिए सराय में नया फर्नीचर, एसी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त एसटीपी की क्षमता बढ़ाना, सभी बाथरूमों की मरम्मत, नए एसी और गीजर, फायर सेफ्टी सिस्टम आदि कार्यों पर लगभग 5 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों के लिए सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है।

कैबिनेट मंत्री श्री हरभजन सिंह ईटीओ ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में अक्टूबर 2026 में भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस बड़े स्तर पर मनाया जाएगा, जिसमें देश-विदेश से श्रद्धालु शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सभी विकास कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएंगे।

इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि जी तीर्थ स्थल श्राइन बोर्ड के एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन श्री बाल जोगी प्रगट नाथ ने कहा कि उन्हें जो सेवा सौंपी गई है, वह उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि यह पावन स्थल अपनी आध्यात्मिक महत्ता के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तीर्थ स्थल के सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस मौके पर विधायक डॉ. जसबीर सिंह संधू, विधायक श्री जसविंदर सिंह रमदास, नशा मुक्ति मोर्चा की माजहा कोऑर्डिनेटर मैडम सोनिया मान, माजहा जोन के सचिव श्री रविंदर हंस, जिला प्रधान एससी विंग डॉ. इंदरपाल सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त श्री रुपिंदरपाल सिंह, जनरल मैनेजर श्री मधुर भाटिया, श्री पवन दराविंद, श्री कुमार दर्शन, एसडीएम मनवीर सिंह ढिल्लों, दलित विकास बोर्ड के चेयरमैन विजय दानव, सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन चंदन ग्रेवाल, पर्यटन अधिकारी श्री सुखमन सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

सरबजीत सिंह सर्वसम्मति से जिला परिषद के चेयरमैन चुने गए

**अमृतसर, 14 मई (साहिल बेरी)

आज बचत भवन, अमृतसर में अतिरिक्त उपायुक्त श्री रुपिंदरपाल सिंह की अध्यक्षता में जिला परिषद के सीधे चुने गए सदस्यों तथा जिले की पंचायत समितियों के चेयरमैनों की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त जनरल-कम-प्रेसाइडिंग अधिकारी द्वारा जिला परिषद अमृतसर के चेयरमैन एवं उप चेयरमैन के चुनाव करवाए गए।

इस चुनाव में सर्वसम्मति से सरबजीत सिंह को जिला परिषद अमृतसर का चेयरमैन चुना गया, जबकि श्रीमती राजविंदर कौर को सर्वसम्मति से जिला परिषद की उप चेयरपर्सन निर्वाचित किया गया।

इस अवसर पर नव-निर्वाचित जिला परिषद अमृतसर के चेयरमैन सरबजीत सिंह और उप चेयरपर्सन श्रीमती राजविंदर कौर ने सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि सदस्यों द्वारा उन पर जताए गए विश्वास पर वे पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने एक स्वर में कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य जिले के गांवों का विकास करना है तथा मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं को अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि वे सभी सदस्यों को साथ लेकर जिले में विकास कार्यों की गति को और तेज करेंगे।

इस मौके पर ब्लॉक समिति वेरका की चेयरपर्सन मैडम नवनीत कौर, जिला परिषद सदस्य सरदार सतनाम सिंह, सरदार मनजीत सिंह, सरदार जसबीर सिंह, सरदार बलजीत सिंह, सरदार लखविंदर सिंह, मैडम प्रियंका, श्रीमती मनदीप कौर, श्रीमती कमलेश रानी सहित पंचायत समितियों हरशा छीना के चेयरमैन सरदार करमजीत सिंह, चोगावां की चेयरपर्सन मैडम भजन कौर, अटारी की चेयरपर्सन श्रीमती मुखविंदर कौर, मजीठा के चेयरमैन सरदार यादवींदर सिंह, सरदार हुसनप्रीत सिंह सियालका, रैया पंचायत समिति के चेयरमैन सरदार हरभजन सिंह, अजनाला की चेयरपर्सन श्रीमती मविंदर कौर तथा जंडियाला पंचायत समिति के चेयरमैन सरदार अमरीक सिंह उपस्थित थे।

कांग्रेस ने विस्थापितों की जनगणना की, अपने सही हक की मांग की, हर इंडसट्रियल जगह गरीबों का घर है: भक्त

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर: कांग्रेस की तरफ से विस्थापितों और आदिवासियों के जल, जमीन, जंगल की रक्षा के लिए निकाली गई गांधीपाठे न्याय पदयात्रा, जो 6 मई को धैनकिया से शुरू हुई थी, 14 तारीख को भुवनेश्वर पहुंची और लोअर PMG चौक पर एक बड़ी जनगणना हुई। इस बड़ी जनगणना में हजारों विस्थापितों और प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, PCC प्रेसिडेंट भक्त चरण दास ने इंडस्ट्रियल जगहों पर हो रहे अमानवीय जुल्म और सरकार की चुप्पी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विकास के लिए इंडस्ट्री ज़रूरी है, लेकिन अमानवीय इस्तेमाल और जुल्म से लोगों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे अपनी मर्ज़ी से ज़मीन, जंगल और पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार उनकी मदद कर रही है। लोग अपनी ज़मीन खो रहे हैं लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ़ धोखा मिल रहा है। ऐसा हो रहा है। श्री दास ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हर उस विस्थापित व्यक्ति को, जिसकी ज़मीन चली गई है, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में शेयर होल्डर बनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि विस्थापन कानून के हिसाब से ग्राम सभा के ज़रिए होना चाहिए और जब तक विस्थापितों को सही मुआवज़ा नहीं मिल जाता, कांग्रेस राज्य के सभी विस्थापितों के हितों और सुरक्षा के लिए लड़ने के इसी रास्ते पर चलती रहेगी। इस जनमत संग्रह में राज्य के अलग-अलग हिस्सों से ठगे गए विस्थापितों ने अपने अनुभव बताए। पीसीसी अध्यक्ष और संगठन प्रभारी संतोष सिंह सलूजा की अध्यक्षता में इदारा मंच में पार्टी के राज्य प्रभारी अजय लल्लू, सह-प्रभारी जेटी कुसुम कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना, पदयात्रा अध्यक्ष सुरेश राउतराय, सांसद सप्तगिरी उलाका, विधायक अशोक दास, विधायक, सीएस राजेन एक्का, मंगू खिल, पूर्व सांसद नागेंद्र प्रधान, पूर्व सांसद अनंत सेठी, इंटक अध्यक्ष रामचंद्र खुंटिया, पूर्व सांसद और अनुसूचित जाति के अध्यक्ष जोशवंत सिंह लागुरी, पूर्व विधायक देवाशीष पटनायक, डॉ ललतेन्दु महापात्रा, पीसीसी उपाध्यक्ष सस्मिता बेहरा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष मीनाक्षी बहिनीपति, युवा कांग्रेस अध्यक्ष रंजीत पात्रा, कोषाध्यक्ष सिद्धार्थ दाश, मीडिया विभाग के अध्यक्ष अरविंद दास, सेवादल के अध्यक्ष सुभेंदु मोहंती, सोशल मीडिया के अध्यक्ष विश्वजीत मोहंती, एरसामा जिला परिषद सदस्य पिनाकी दास, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यव्रत पात्रा, भुवनेश्वर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश जेना, प्रेसिडेंट राजीव पटनायक, जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट देवी प्रसाद नायक, क्योंझर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मनोज जेना, अंगुल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट सुनील प्रधान, लेजिस्लेटिव कैंडिडेट निरंजन नायक, जगतसिंहपुर लेजिस्लेटिव कैंडिडेट नलिनी स्वैन, सीनियर कांग्रेस लीडर असित पटनायक वगैरह सभी स्पीकर्स ने अपने भाषणों में डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी पर सरकार के रुख की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आलोचना की और विस्थापितों के लिए कांग्रेस के कमिटमेंट का ऐलान किया।

बी.एस.एफ. द्वारा अजनाला में "स्पंदन लीग–2026" पुरुष कबड्डी चैम्पियनशिप का भव्य शुभारंभ

महानिरीक्षक डॉ. अतुल फुलझेले ने चैम्पियनशिप एवं "प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र" का उद्घाटन किया
खेल राष्ट्रीय एकता और नशा-मुक्त समाज निर्माण का प्रभावी माध्यम – डॉ. अतुल फुलझेले

अजनाला, 14 मई (साहिल बेरी)

सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) पंजाब द्वारा आज बी.एस.एफ. परिसर अजनाला में अंतर तहसील, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय पुरुष कबड्डी चैम्पियनशिप "स्पंदन लीग–2026" का भव्य शुभारंभ किया गया। इस चैम्पियनशिप का विधिवत उद्घाटन डॉ. अतुल फुलझेले, महानिरीक्षक, बी.एस.एफ. पंजाब द्वारा किया गया। यह प्रतियोगिता भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) के सहयोग से आयोजित की जा रही है।

उद्घाटन समारोह में श्री एस.एस. चंदेल, डी.आई.जी. बी.एस.एफ. अमृतसर, श्री अंकित गोयल, डी.आई.जी. बी.एस.एफ. गुरदासपुर, विभिन्न खेल अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में बी.एस.एफ. जवान, स्कूली छात्र एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

इस अवसर पर खिलाड़ियों एवं दर्शकों को संबोधित करते हुए महानिरीक्षक डॉ. अतुल फुलझेले ने कहा कि खेल केवल शारीरिक फिटनेस का माध्यम ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, अनुशासन एवं नशा-मुक्त समाज निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को निष्पक्ष खेल एवं खेल भावना की शपथ भी दिलाई तथा "नशा मुक्ति अभियान" के महत्व पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने बताया कि इस चैम्पियनशिप में पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से 16 जूनियर एवं 11 सीनियर टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें लगभग 325 खिलाड़ी एवं खेल अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे खेल आयोजन युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के साथ-साथ उन्हें नशे से दूर रखने में भी सहायक सिद्ध होते हैं।

इस दौरान मुख्य अतिथि डॉ. अतुल फुलझेले द्वारा अजनाला परिसर के मुख्य द्वार पर "प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र" का भी उद्घाटन किया गया। इस केंद्र के माध्यम से बी.एस.एफ. कर्मियों एवं स्थानीय निवासियों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

_ कुछ दर्द ऐसा भी_

दिन–रात मेहनत की हमने,
नींद भी अपनी हार गई,
लेकिन कुछ लोगों की गलती से,
मेहनत सारी बेकार गई।

जब खबर मिली पेपर लीक का, दिल जैसे टूट गया,
जिस भरोसे से परीक्षा दी,
वो भरोसा ही छूट गया।

कितनों ने आँसू छुपाए होंगे, कितनों ने दर्द सहा होगा,
किसी ने डॉक्टर बनने का सपना,
चुपचाप दिल में रखा होगा।

फिर से वही किताबें खोलो, फिर से वही इम्तिहान होगा, लेकिन इस टूटे मन के अंदर,
कितना भारी तूफान होगा।

ऐ खुदा, इतना न्याय तो कर, मेहनत कभी न हार जाए, जिसने सच में मेहनत की हो, उसका सपना

साकार हो जाए।

बच्चों के इन टूटे दिलों की, बस इतनी सी पुकार है,
ईमानदारी से हो परीक्षा,
यही सबका अधिकार है।

अदिति कुशवाह..

केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के लिए रेलवे विस्तार की बड़ी पहल की घोषणा की

मनोरंजन शासमल ,स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर : केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओडिशा में किए जा रहे बड़े रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की पहल के बारे में बताया।

नई 18407/18408 पुरी–कोरापुट–पुरी तीन हफ़्ते में एक बार चलने वाली एक्सप्रेस की शुरुआत की घोषणा करते हुए, श्री वैष्णव ने कहा कि यह सर्विस पहली बार पुरी और पश्चिमी और दक्षिणी ओडिशा के बड़े हिस्सों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी देगी।

यह ट्रेन खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, अंगुल, संबलपुर, बरगढ़ रोड, बलांगीर, टिटलागढ़, केसिंगा, मुनिगुडा, रायगड़ा, टिकिरी, लक्ष्मीपुर रोड, काकिरीगुमा और दमनजोड़ी होते हुए चलेगी, जिससे तटीय, पश्चिमी और दक्षिणी ओडिशा के यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा होगा।

यह ट्रेन खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, अंगुल, संबलपुर, बरगढ़ रोड, बलांगीर, टिटलागढ़, केसिंगा, मुनिगुडा, रायगड़ा, टिकिरी, लक्ष्मीपुर रोड, काकिरीगुमा और दमनजोड़ी होते हुए चलेगी, जिससे तटीय, पश्चिमी और दक्षिणी ओडिशा के यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इस सर्विस से तीर्थयात्रा, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थकेयर, नौकरी और बिजनेस ट्रैवल के लिए कनेक्टिविटी बेहतर होगी, खासकर KBK इलाके और आदिवासी बहुल जिलों के लिए।

ओडिशा में रेलवे की ग्रोथ के बारे में बताते हुए, श्री वैष्णव ने बताया कि राज्य में अभी करीब ₹90,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मुख्य प्रोजेक्ट में जूनागढ़-नबरंगपुर, नबरंगपुर-जयपुर, जयपुर-मलकानगिरी, बरगढ़-नुआपाड़ा, गुनुपुर-थेरुबली, खुर्दा रोड-बलांगीर और बिमलागढ़-तालचेर रेल लाइन प्रोजेक्ट शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि लंबे समय से रुका हुआ खुर्दा रोड-बलांगीर रेल लाइन प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसे 2027 तक पूरा करने का टारगेट है।

मंत्री ने ओडिशा से होकर हावड़ा-चेन्नई मेन कॉरिडोर पर चल रहे चार लाइनिंग के काम के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि नई लाइनों और बड़े कैपेसिटी बढ़ाने के काम के पूरा होने के बाद, ओडिशा में भविष्य में करीब 500 और ट्रेनें चलाने की कैपेसिटी होगी।

श्री वैष्णव ने आगे बताया कि अमृत स्टेशन स्कीम के तहत ओडिशा के 59 रेलवे स्टेशनों को फिर से डेवलप किया जा रहा है, जिसमें भुवनेश्वर, पुरी, संबलपुर, बरहामपुर, तालचेर और बारीपदा स्टेशन शामिल हैं। प्रस्तावित पुरी-कोणार्क रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए एक नई DPR भी तैयार की जा रही है। उन्होंने ओडिशा में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023